हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 01 | अंक - 351 | बेमेतरा, गुरुवार 07 अगस्त 2025 | रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित | कुल पेज - 8 | मूल्य - 5 रूपये

पहला कॉलम

गुरमीत राम रहीम एक बार फिर 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर

नई दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर सुनारिया जेल से बाहर आ गया है। इस बार उन्हें 40 दिन की पैरोल दी गई है। जेल से रिहा होने के बाद वे पुलिस सुरक्षा में अपने सिरसा स्थित डेरे के लिए रवाना हुए। राम रहीम को इससे पहले 9 अप्रैल 2025 को 21 दिन की फरलो मिली थी। अब तक वह 14 बार जेल से बाहर आ चुके हैं। इस साल 1 जनवरी से 14 सितंबर तक के चार महीने की अवधि में वह 91 दिन जेल से बाहर रहेंगे। डेरा प्रमुख साल 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। उन्हें पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने साध्वियों से बलात्कार और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में दोषी ठहराया था। उन्हें 20-20 साल की दो सजाएं सुनाई गई हैं। पैरोल की शर्तों के तहत राम रहीम सिरसा डेरे में ही रहेंगे। जानकारी के मुताबिक, इस बार पैरोल की अवधि के दौरान वह 15 अगस्त को अपना 58वां जन्मदिन मनाएंगे और डेरे में पूरे महीने कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

बिहार वोटर लिस्ट में अनियमितताएं ठीक नहीं हुईं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

पटना। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को ठीक नहीं किया गया, तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यह किसी एक पार्टी की बात नहीं है - यह लोकतंत्र को बचाने की बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि मृत मतदाताओं के नाम शामिल कर लिए गए जबकि विशिष्ट समुदायों के नाम हटा दिए गए। तेजस्वी ने यह भी कहा कि राजद और उसके सहयोगी चुनाव आयोग को साक्ष्य के साथ शिकायत सौंपेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से मिले नोटिस की पुष्टि की और कहा कि वह इसका जवाब देंगे। तेजस्वी ने कहा, जवाब दिया जाएगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कई नाम गायब हैं।

महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने 27प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को दी मंजूरी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा कि महाराष्ट्र के सभी नगर निकाय चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू रहेगा। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा की गई नई प्रभाग रचना (वार्ड बंटवारा) को भी वैध ठहराया गया है। कोर्ट के इस फैसले से मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर समेत पूरे महाराष्ट्र में रुके हुए नगर निकाय चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। पिछले कुछ समय से राज्य में नगर निकाय चुनाव नहीं हो पा रहे थे। इसका कारण था नई वार्ड रचना और ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया।

पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया

सरकारी मंत्रालयों...विभागों को मिला नया ठिकाना-पीएम मोदी

नई दिल्ली/ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दस नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरियट भवनों में से पहले, कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया। इस नए पावर कॉम्प्लेक्स में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग स्थित होंगे, जो वर्तमान में दिल्ली भर में स्थित हैं। कर्तव्य भवन को दिल्ली भर में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले उद्घाटन किए जाने वाले कर्तव्य भवन-3 में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय होंगे। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक स्थित मंत्रालयों को कर्त्तव्य भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे रेज़िन हिल स्थित दोनों ब्लॉकों को एक संग्रहालय में बदलने का रास्ता साफहो जाएगा, जहाँ भारतीय पौराणिक और आधुनिक इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। कई प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय वर्तमान में शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी पुरानी इमारतों से संचालित होते हैं, जिनका निर्माण 1950 और 1970 के दशक के बीच हुआ था। सरकार के अनुसार, इन इमारतों को अब संरचनात्मक रूप से पुराना और अक्षम माना जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एचयूए) ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (सीसीएस) के अंतर्गत दस भवनों के निर्माण की योजना शुरू की है। इनमें से भवन 2 और 3 निर्माणाधीन हैं और अगले महीने तक पूरा होने की उम्मीद है। सीसीएस भवन 10 का काम अगले साल अप्रैल तक पूरा होने वाला है, जबकि भवन 6 और 7 का निर्माण अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि वर्तमान में शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन में कार्यरत कार्यालयों को निर्माण चरण के दौरान दो वर्षों की अवधि के लिए अस्थायी रूप से चार नए स्थानों, कस्तूरबा गांधी मार्ग, मिंटो रोड और नेताजी पैलेस में स्थानांतरित किया जाएगा।

7 साल बाद 31 अगस्त को चीन जाएंगे पीएम मोदी,एससीओ की बैठक में होंगे शामिल, जिनपिंग से हो सकती है मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन शहर में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन का दौरा करेंगे। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद यह उनकी पहली चीन यात्रा होगी। उन्होंने पिछली बार 2019 में चीन का दौरा किया था।एससीओ सदस्य देशों के साथ चर्चा में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत-चीन संबंधों में स्थिरता और संवाद बहाल करने के प्रयास किए जाएँगे। शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अनौपचारिक मुलाकात की संभावना है। इससे पहले, अक्टूबर 2024 में, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मिले थे। इसके बाद, दोनों देशों के बीच सीमा तनाव कम करने के प्रयासों में तेज़ी आई।

खरगे बोले-सरकार इच्छुक नहीं

बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण पर संसद में चर्चा चाहता है विपक्ष..

नई दिल्ली/ एजेंसी

विपक्षी दलों की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी राज्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर राज्यसभा में चर्चा की माँग दोहराई है। बुधवार को उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को पत्र लिखकर खड़गे ने कहा कि यह मुद्दा करोड़ों मतदाताओं, खासकर समाज के कमज़ोर वर्गों के मतदाताओं के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे उच्च सदन के सभापति के पिछले फैसलों ने सदन को एक प्रतिबंध के साथ, दुनिया की हर चीज़ पर चर्चा करने की अनुमति दी है। उपसभापति को लिखे अपने पत्र के कुछ अंश साझा करते हुए, खड़गे ने लिखा, निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा सबसे पहले बिहार में की जा रही है और फिर इसे पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में भी किया जाएगा। विपक्षी सांसद मौजूदा सत्र के पहले दिन से ही सदन में इस पर तत्काल चर्चा की माँग कर रहे हैं। अपने पत्र में उन्होंने आगे कहा कि इसलिए, मैं अपनी ओर से और राज्यसभा में विपक्षी दलों की ओर से, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा की अनुमति दें, जो करोड़ों मतदाताओं, विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों के मतदाताओं के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। उपसभापति से उच्च सदन के सभापति के पिछले फैसलों को बरकरार रखने का आग्रह करते हुए, खड़गे ने लिखा कि 21 जुलाई, 2023 को, राज्यसभा के तत्कालीन सभापति ने एक फैसला दिया था। कि 'यह सदन एक प्रतिबंध के साथ दुनिया की हर चीज़ पर चर्चा करने का हकदार है'। खड़गे ने उस परंपरा को जारी रखने का आह्वान करते हुए।

बिहार में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम

शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से शनिवार तक मांगी जानकारी.....

नई दिल्ली। एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग (ईसी) को निर्देश दिया है कि वह बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए करीब 65 लाख मतदाताओं की पूरी जानकारी 9 अगस्त तक पेश करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह जानकारी उन राजनीतिक दलों के साथ-साथ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) नाम की एनजीओ को भी दी जाए, जिसने इस मुद्दे पर याचिका दाखिल की है। चुनाव आयोग ने बिहार में 24 जून को 'विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर)' शुरू किया था। इसके तहत 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, जिसमें 7.24 करोड़ मतदाता दिखाए गए। लेकिन इसमें से 65 लाख से अधिक वोटरों के नाम हटा दिए गए। चुनाव आयोग का कहना है कि ये लोग या तो मर चुके हैं, दूसरी जगह स्थायी रूप से चले गए हैं, या दो जगहों पर नाम था। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुयान और एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा, 'हमें हर उस वोटर की जानकारी चाहिए जिसका नाम हटाया गया है। ये देखें कि किस आधार पर नाम हटे हैं।' वहीं एनजीओ की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि, 'राजनीतिक पार्टियों को हटाए गए वोटरों की लिस्ट दी गई है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि कौन मरा है, कौन शिफ्ट हुआ है, या किसका नाम गलत तरीके से हटा।' कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि वह 9 अगस्त तक जवाब दाखिल करे।

एडीआर की याचिका में क्या मांग की गई

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मांग की है कि 65 लाख हटाए गए नामों की पूरी सूची प्रकाशित की जाए। हर नाम के साथ यह भी बताया जाए कि उसे क्यों हटाया गया, मौत, स्थायी स्थानांतरण या कोई अन्य वजह। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हलफनामा देकर कहा, 'हम वोटर लिस्ट को साफकरने का काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि अपात्र लोग हटें और केवल सही लोग वोटर लिस्ट में रहें।

पार्टी की छवि धूमिल करने का हो रहा प्रयास

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बयान जारी कर अपनी पार्टी की स्वतंत्र राजनीतिक नीति को दोहराया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएसपी न तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के साथ है और न ही कांग्रेस के इंडी गठबंधन से जुड़ी है। मायावती ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांतों पर चलती है, जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए समर्पित है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा।

गर्जना के साथ जमकर बादल गरजे

रायपुर के महादेव घाट में पहली बार दिखा ऐसा नजारा... काली घटाओं के साथ एक घंटे तक जमकर गरजे बादल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार की शाम 5 बजे के बाद तेज गर्जना के साथ जमकर बादल गरजे। इस दौरान रायपुर के कमल विहार समेत कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। वहीं रायपुरा क्षेत्र में इस साल पहली बार ऐसा नजारा देखा गया जिसे देखकर लोग अंचभित रह गये। यहां काली घटाओं के साथ करीब एक घंटे तक बादल लगातार हल्के-हल्के गरजते रहे। लोगों का कहना था कि जिस तरह से प्लेन में बैठने पर हवाई जहाज के चलने पर गड़गड़ाहट होती रहती है, ठीक उसी तरह करीब एक घंटे तक रायपुरा क्षेत्र में बादलों की गड़गड़ाहट जारी रही। आसमान चारों तरफ काली घटायें छाई हुई थी। बादल लगातार गरज रहे थे। इस दौरान बीच-बीच में हल्की-हल्की बिजली भी चमक रही थी। आसमान में घने काले बादल छाये रहने और बादल गरजने के बाद भी रायपुरा क्षेत्र में बारिश नहीं हुई बल्कि नाममात्र की बूंदाबांदी होती रही। इस संबंध में अमर उजाला ने मौसम विज्ञानी से बातचीत की। मौसम एक्सपर्ट एचपी चंद्रा ने बताया कि यह मुख्य रूप से बादलों में अचानक से तापमान में बदलाव के कारण होता है। यह तब होता है जब दो अलग तरह के बादल आस-पास आ जाते हैं, जिसमें एक गर्म और दूसरा ठण्डा होता है। यानी अधिक गर्मी और उमस की वजह से भी ऐसा सिस्टम बन जाता है। बादल आपस में टकराने से भी ध्वनि निकलती रहती है। अचानक से ऊर्जा बाहर निकलने लगती है और इसी कारण चमक और गरज के साथ बिजली भी गिरती है।

इस चित्र में एआईसीसी द्वारा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा पार्टी नेता राहुल गांधी नई दिल्ली में इंडिया अलायंस के फ्लोर नेताओं की बैठक के दौरान।

एसआईआर मामले

भाजपा-नीत केंद्र सरकार के दिमाग की है उपज.....

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से भाजपा-नीत केंद्र सरकार के दिमाग की उपज है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित घाटल के दौरे पर आईं बनर्जी ने यह भी कहा कि बांग्ला भाषी भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी बताकर पड़ोसी देश भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा, ''यह योजना केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है, जिसमें निर्वाचन आयोग को भी शामिल किया गया है। हम इससे सहमत नहीं हैं।''उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रक्रिया के लिए माता-पिता के जन्म प्रमाण-पत्र सुरक्षित रखना सभी के लिए संभव नहीं है।

राहत बचाव कार्यों में जुटे 225 से अधिक जवान..

उत्तरकाशी में जलप्रलय-मलबे के बीच जिंदगी की तलाश

उत्तराखंड/ एजेंसी

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जारी भारी बारिश के बीच बुधवार सुबह धराली में आपदा पीड़ितों की तलाश के लिए बचाव एवं राहत कार्य फिर शुरू किया गया। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। मंगलवार दोपहर बाद बादल फटने से खीरगंगा नदी में आयी भीषण बाढ़ में करीब आधा गांव तबाह हो गया था। धराली गंगोत्री धाम से करीब 20 किलोमीटर पहले पड़ता है और यात्रा का प्रमुख पड़ाव है। उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, विनाशकारी बाढ़ में चार लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि विभिन्न एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे बचाव अभियान में 130 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, बाढ़ में 50 से अधिक लोग लापता हो सकते हैं क्योंकि पानी के अचानक आने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का मौका ही नहीं मिला।हालांकि, घटनास्थल पर जमा मलबे से अभी तक कोई शव बरामद नहीं हुआ है। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि लापता लोगों में 11 सैनिक भी शामिल हैं। 14 राज रिफके कमांडिंग अधिकारी कर्नल हर्षवर्धन 150 सैनिकों की अपनी टीम के साथ मौके पर राहत और बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीवास्तव ने कहा कि सैनिकों के लापता होने और बेस के प्रभावित होने के बावजूद टीम पूरे साहस और दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए भारतीय सेना ने एमआई-17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। मुख्यमंत्री धामी बुधवार को स्वयं धराली बाजार, हर्षिल तथा आसपास के क्षेत्रों में आपदा से हुई क्षति का निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों ने यहां बताया कि आपदा में हुए जानमाल के भारी नुकसान को देखते हुए राहत एवं बचाव कार्यों तथा क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की तत्काल मरम्मत के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से 20 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गयी है। प्रदेश की स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने पांच विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम को तत्काल उत्तरकाशी पहुंचने के निर्देश दिए हैं। ताकि प्रभावितों को समय से उचित इलाज उपलब्ध कराया जा सके। इन डॉक्टरों में एक जनरल शल्यचिकित्सक और दो हड्डीरोग शल्यचिकित्सक शामिल हैं।

बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग की पहल

15 दिवसीय नि:शुल्क प्रशिक्षण का समापन, स्तनपान सप्ताह पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

बेमेतरा/मूक पत्रिका

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर चलाए गए 15 दिवसीय निःशुल्क ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण का समापन ग्राम भिंभौरी के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में किया गया। यह प्रशिक्षण 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (हब) द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी चंद्रबेश सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में संचालित हुआ। इस प्रशिक्षण में कुल 34 इच्छुक किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं ने भाग लिया। मास्टर ट्रेनर श्रीमती संगीता सिंह द्वारा उन्हें थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, फेशियल, मेकअप, ब्लीच, मैनीक्योर, पैडीक्योर, वैक्स आदि का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समापन अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष संदीप परगनिहा एवं पार्षद गोविन्द यदु द्वारा प्रशिक्षार्थियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। इसी अवसर पर विश्व स्तनपान सप्ताह (1 से 7 अगस्त 2025) के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र व आरएचओ के संयुक्त तत्वावधान में गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें माताओं को शिशु को जन्म के तुरंत बाद दिया जाने वाला पहला पीला गाढ़ा दूध (कोलेस्ट्रम) एवं 6 माह तक केवल स्तनपान कराने के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही 'रेडी टू ईट' पोषण आहार, तिरंगा भोजन, स्थानीय साग-सब्जियां और फलों के पोषण संबंधी लाभ बताए गए जिससे मां एवं बच्चा दोनों सुपोषित और स्वस्थ रहें। कार्यक्रम में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इसमें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, महिला कोष की सक्षम योजना एवं ऋण योजना प्रमुख रहीं। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक चल रहे विशेष पंजीकरण अभियान के अंतर्गत बताया गया कि पहली बार मां बनने पर 5000 रुपये की सहायता (3000 रुपये गर्भावस्था पंजीकरण के 6 माह बाद तथा 2000 रुपये 14 सप्ताह के टीकाकरण के बाद) तथा दूसरी बार बालिका जन्म लेने पर एकमुश्त 6000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इच्छुक महिलाएं अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या मितानिन से संपर्क कर योजना का लाभ ले सकती हैं। इस अवसर पर उप स्वास्थ्य केन्द्र से सीएचओ श्रीमती गोदावरी वर्मा, आरएचओ राकेश बन्छोर, जेंडर विशेषज्ञ श्रीमती सेवन्तिका साहू, सखी केसवर्कर तमन्ना, पर्यवेक्षक श्रीमती रश्मि वर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाएं तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, पोषण जागरूकता और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक प्रभावी प्रयास के रूप में सराहनीय पहल रहा।

बने खाबो-बने रहिबो अभियान के तहत होटल, ढाबा स्ट्रीट फूड वेंडर्स की जांच

जन जागरूकता अभियान चलाया गया

कांकेर /मूक पत्रिका

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के मार्गदर्शन में ÷बने खाबो-बने रहिबो÷ के तहत कांकेर जिले में भी विशेष जांच एवं जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्ट्रीट फूड वेंडर्स, खाद्य परोसने वाले संस्थान, रेस्टोरेंट, ढाबा और होटलो का निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने पर जैसे अखबारी कागज का उपयोग, बासी खाद्य पदार्थों का उपयोग, पिलाये जाने वाले पानी की जांच, वेज-नान वेज-खाद्य पदार्थों की अस्वच्छ हैंडलिंग इत्यादि के दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई, साथ ही आम जनता को खाद्य पदार्थों से संबंधित जानकारी दिया गया। खाद्य नमूना के रूप में 07 सेम्पल जांच लिया गया। इस कार्यवाही में खाद्य औषधि प्रशासन विभाग कांकेर खाद सुरक्षा अधिकारी भारत भूषण पटेल सहित विभाग की टीम के अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे।

जिले में अब तक 329 मिमी. औसत वर्षा दर्ज

बेमेतरा। चालू बारिश सीजन के दौरान बेमेतरा जिले में 01 जून से 06 अगस्त 2025 प्रतिवेदित दिनांक तक की स्थिति में सवेरे 8.00 बजे तक जिले में 329 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। जिले में अब तक सर्वाधिक वर्षा तहसील थानखम्हरिया में 474.3 मि.मी. तथा न्यूनतम 246.5 मि.मी. वर्षा भिंभौरी तहसील में दर्ज की गई है। संयुक्त जिला कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेमेतरा तहसील मे 261.1 मि.मी. वर्षा, नांदघाट तहसील में 348 मि.मी. वर्षा, बेरला तहसील में 315.4 मि.मी., देवकर तहसील में 306 मि.मी, वर्षा दाढ़ी तहसील मे 395.1 मि.मी., वर्षा नवागढ़ तहसील में 255 मि.मी. एवं साजा तहसील में 359.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है।

प्रतापपुर में हुआ गायत्री प्रज्ञा पीठ का भूमिपूजन

सूरजपुर/प्रतापपुर/मूक पत्रिका

बहुप्रतिक्षीत गायत्री प्रजा पीठ निर्माण हेतु भूमि पूजन। विधिवत मंत्रोचार व हवन पूजन के साथ सम्पन्न हुआ जिसमें अम्विकापुर से पधारे उपजोन प्रभारी एस. जे. दुवेदी व जी.पी. स्वर्णकार तथा दीदी श्रीमती शारदा डिवेदी के मुखाग्रबीन मन्त्रोचार से विधिवत सम्पन्न कराया गया। जिसमें मुख्य यजमान नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मानती योगेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष अजीत शरण सिंह सह पत्नी, संतोष कुमार निवारी सह पत्नी, नवीन अग्रवाल सहपत्नी, अखिलेश निवारी सह पत्नी ने हवन कुण्ड का पूजन कर आहुतियां दी। कार्यक्रम में उपस्थित गायत्री परिवार के ब्लाक समन्वयक शैलेन्द्र सिंह, महेश्वरी लाल उईके, श्रवण मिश्रा, राधिका शरण सिंह, देवेन्द्र निवारी, कमलेश शुक्ला, विमल भाई, वंश लाल, मोती लाल, शा. कालीदास महाविद्यालय प्राचार्य रजनीश प्रसाद सिंह, अनुजेश्वर पाण्डेय, लालबहादूर गुप्ता, नवीन जायसवाल, दिलीप गुप्ता, नवीन नाविक, उमेश जायसवाल, जे.पी.नामदेव, रामकुमार राजवाडे, त्रिपुरेश्वर निवारी महावीर निवारी, अखिलेश वर्मा तथा महिला मण्डल से श्रीमति मनोरमा सिंह, श्रीमती आशा शुक्ला, श्रीमती कुन्ती पाण्डेय, श्रीमती पूजा मिश्रा, श्रीमती मुन्नी देवी, श्रीमती लक्ष्मी तिवारी व अज्जू नाइडू, मदन गर्ग आदि ने सराहनीय योगदान व अपना बहुमूल्य समय देकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सतीश मित्तल, सहयोग दिया।

महारानी अस्पताल के शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य संस्थान में चार जुड़वा नवजात शिशुओं को मिला जीवनदान

सुकमा जिले की दशमी कवासी के चार जुड़वा शिशुओं को जन्म के बाद थी श्वसन की दिक्कत, एक महीने तक एसएनसीयू में दी गई लाईफसपोर्ट

जगदलपुर /मूक पत्रिका

महारानी अस्पताल जगदलपुर के शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य संस्थान की समुचित देखभाल एवं एसएनसीयू में एक महीने तक दी गई लाईफसपोर्ट के फलस्वरूप आज दशमी कवासी के चार जुड़वा बच्चे स्वस्थ एवं तंदुरुस्त हैं और मां दशमी कवासी के साथ परिजन महारानी अस्पताल के चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टॉफकी मानवीय संवेदनाओं के साथ दिए गए सेवाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मंगलवार को महारानी अस्पताल के निरीक्षण में पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इन चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टॉफकी संवेदनशील सेवाओं को सराहना करते हुए उन्हें बस्तर अंचल की जनता को अनवरत बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्साहवर्धन किया। ज्ञात हो कि साल भर पहले 25 जुलाई 2024 को जगदलपुर में सुकमा जिले के तोंगपाल थाना अंतर्गत ग्राम जैमर निवासी श्रीमती दशमी कवासी ने एक निजी अस्पताल में सिज़ेरियन ऑपरेशन के माध्यम से चार जुड़वा शिशुओं (क्वाड्रप्लेट्स) को जन्म दिया था। जन्म के समय उक्त चारों नवजातों का वजन अत्यंत कम था। इन चार शिशुओं में 2 लड़के और 2 लड़कियाँ थीं, जिनका जन्म के समय वजन क्रमशः 1.3 किलोग्राम, 1.2 किलोग्राम, 1.1 किलोग्राम और 1.25 किलोग्राम था। जन्म के तुरंत बाद सभी शिशुओं को साँस लेने में कठिनाई (श्वसन संकट) उत्पन्न हो गया, जिस कारण उन्हें विशेष देखभाल हेतु महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन चारों में से एक बच्ची की हालत गंभीर थी, जिसे पुनर्जीवन की आवश्यकता पड़ी। तीन शिशुओं को सीपीएपी पर रखा गया और एक को वेंटिलेटर सपोर्ट देना पड़ा। इन बच्चों के इलाज हेतु आवश्यक सभी दवाइयाँ और जाँचों की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा सीजीएमएससी के माध्यम से की गई। महारानी अस्पताल की समर्पित चिकित्सकों और नर्सेस टीम ने इन नन्हें जीवनों को बचाने के लिए निरंतर निगरानी, ऑक्सीजन सपोर्ट और पोषण प्रबंधन प्रदान किया। मां दशमी कवासी और अस्पताल के स्टाफ के अथक प्रयासों से चारों शिशुओं की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ और एक महीने बाद उन्हें वजन बढ़ने के साथ स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। छुट्टी के समय उनका वजन था: 1.79 किलोग्राम, 1.53 किलोग्राम, 1.3 किलोग्राम और 1.6 किलोग्राम था। अब उक्त चारों बच्चे स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी रहे हैं। यह कहानी चिकित्सा सेवा, एक मां के प्रेम और समुदाय के सहयोग की शक्ति का सजीव प्रमाण है। यह उन परिवारों के लिए आशा की किरण है, जो इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और यह दर्शाती है कि समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने से नाजुक से नाजुक जीवन भी संवर सकता है।

कलेक्टर जनदर्शन में मिले 43 आवेदन प्राप्त आवेदनों को शीघ्र निराकृत करने विभागीय अधिकारियों को निर्देश

कांकेर/मूक पत्रिका

- जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक कलेक्टर जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आवेदकों ने अपनी विभिन्न मांगों एवं समस्याओं को लेकर कुल 43 आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के लिए निर्देशित किया। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर के ग्राम पंचायत डोंगरकट्टा के सरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा प्राथमिक शाला बयानार जो कि पहले संचालित हो रहा था, जो आज की स्थिति में बंद है अतः उक्त विद्यालय को पुनः संचालित कराने तथा गांव में मोबाईल टावर लगवाने के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार विभिन्न ग्रामों के ग्रामीणों द्वारा अतिक्रम हटाने, आर्थिक सहायता राशि दिलाने, शेड निर्माण की राशि दिलाने, हैण्ड खनन कराने, आर्थिक सहायता राशि दिलाने, सोलर पंप तथा शौचालय निर्माण कराने, प्रोत्साहन राशि दिलाने जैसे विभिन्न प्रकार की मांगों व समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर डीएफओ हेमचंद पहारे, अग्रवाल, अपर कलेक्टर जितेन्द्र कुरें एवं ए.एस. पैकरा सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी तथा जिला स्तर के अधिकारीगण मौजूद रहे।

नालसा वीर परिवार सहायता योजना अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को मिलेगा निःशुल्क जानकारी-जिले के भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं, वर्तमान में सेवारत सैनिकों एवं उनके आश्रित परिजनों सहित थलसेना, जलसेना और वायुसेना से संबंधित सभी सैनिक परिवारों को के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी संजय शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सैनिक परिवारों की कानूनी समस्याओं का समाधान के लिए नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 लागू की गई है, यह सेवा पूर्णतः निशुल्क प्रदान की जा रही है। जो भी सैनिक परिवार किसी प्रकार की कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं, वे जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कांकेर में कार्यालीन समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं। वहां उनकी समस्याओं को दर्ज कर विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह पहल उन सैनिक परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, जो विभिन्न कानूनी मामलों में मार्गदर्शन या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं।

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने ली मैदानी समीक्षा, दिए प्रभावशाली आयोजन के निर्देश

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बीते बुधवार को 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन हेतु जिला मुख्यालय स्थित बेसिक स्कूल मैदान में पहुंचकर तैयारियों की मैदानी समीक्षा की और वही स्थित गाँधी भवन मे अधिकारीयों से चर्चा की । इस दौरान उन्होंने समस्त जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने मैदान में आयोजित होने वाले फाइनल रिहर्सल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सद्भावना दौड़ एवं सद्भावना मैच की तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों, विद्यार्थियों एवं युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित हों कि हर वर्ग में देशभक्ति और सामाजिक एकता की भावना जागृत हो।उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि 13 अगस्त को अंतिम रिहर्सल, 14 अगस्त की शाम ÷एक शाम शहीदों के नाम÷ एवं सांस्कृतिक-देशभक्ति कार्यक्रमों को प्रभावशाली, अनुशासित और जन-सहभागिता से परिपूर्ण बनाया जाए।कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि 14 और 15 अगस्त की रात समस्त शासकीय कार्यालयों एवं भवनों में प्रकाश व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि राष्ट्रीय पर्व की गरिमा और उल्लास सभी तक पहुंचे। कलेक्टर शर्मा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित, गरिमामय और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, शिक्षा, जनसंपर्क, नगर पालिका, स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

शिक्षा विभाग की साख पर सवाल!

2 माह में एक व्याख्याता के युक्तियुक्त के तहत 4 बार संशोधन, शिक्षकों में आक्रोश, शिक्षा विभाग बना मजाक

सूरजपुर/प्रतापपुर/मूक पत्रिका

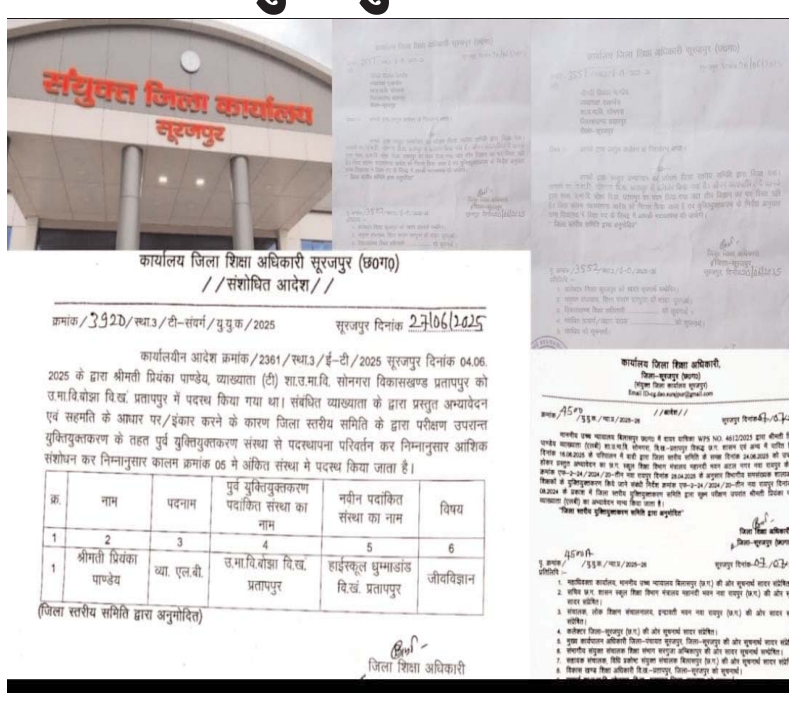

प्रशासनिक मज़ाक-शुरुआत से ही जिले में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया मनमाने ढंग से संचालित की जा रही है। कई शिक्षकों को बिना स्पष्टीकरण के अतिशेष घोषित कर दिया गया। कुछ शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में भेजा गया, जहां पद रिक्त ही नहीं थे, या उन्हें एक ही पद पर कई बार अलग-अलग आदेश जारी किए गए।

व्याख्याता प्रियंका पांडे का मामला बना प्रशासनिक हास्य का केंद्र-व्याख्याता प्रियंका पांडे के संदर्भ में तो प्रशासन ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं –केवल 2 महीनों में उनके लिए 4 बार पदस्थापन आदेश जारी किए गए, जिससे शिक्षक समाज में भ्रम, उपहास और रोष की स्थिति बनी।

1. पहला आदेश - 4 जून 2025: शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोझा ङ्क जबकि वहां कोई पद रिक्त नहीं था।

2. दूसरा आदेश - 20 जून 2025: हाई स्कूल सोनगरा में यथावत रखने का आदेश।

3. तीसरा आदेश - 27 जून 2025: उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धुमाडाड़ में पदस्थापना।

4. चौथा आदेश - 7 जुलाई 2025: पुनः उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनगरा के लिए मान्य किया गया अंतिम आदेश।

प्रशासनिक नियमों के अनुसार एक बार आदेश जारी होने के बाद केवल संशोधन किया जाना चाहिए, परंतु बार-बार पदस्थापन बदलने से यह पूरी प्रक्रिया शिक्षकों के बीच एक हास्य का विषय बन गई है।

शिक्षक संघों और कर्मचारियों में भारी असंतोष-शिक्षक संघों द्वारा लगातार विरोध के बावजूद शिक्षा विभाग के रवैये में कोई सुधार नहीं हुआ।

संघों का आरोप है कि –÷यह प्रक्रिया न केवल अपारदर्शी और पक्षपातपूर्ण है, बल्कि इससे ईमानदारी से काम करने वाले शिक्षक हताश हो रहे हैं।÷

जनप्रतिनिधि और समाज भी नाराज-आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि –÷जिला शिक्षा अधिकारी के गलत निर्णयों और अड़ियल रवैये से जिले की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है।÷÷विद्यालयों में शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन एक व्याख्याता को चार बार इधर से उधर करना समझ से परे है।÷

शिक्षा विभाग की गरिमा को ठेस - यही विभाग जब मतदाता सूची, जनगणना, चुनाव ड्यूटी जैसे संवेदनशील कार्यों में अग्रणी रहता है, तो उसे अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं में भी पारदर्शिता और जिम्मेदारी दिखानी चाहिए।

लेकिन वर्तमान में विभाग न केवल अपनी गरिमा खो रहा है, बल्कि उसके निर्णय समाज में अविश्वास की भावना भी बढ़ा रहे हैं।

शिक्षा व्यवस्था को मजाक बनने से रोका जाए -शिक्षा विभाग की यह स्थिति न केवल प्रशासनिक अक्षमता का प्रतीक है, बल्कि जन विश्वास को कमजोर करने वाली भी है। शिक्षक समाज, जनप्रतिनिधि और जागरूक नागरिक मांग कर रहे हैं कि – जिला शिक्षा अधिकारी के निर्णयों की जांच हो,युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया की निष्पक्ष समीक्षा की जाए,और शिक्षा विभाग की साख बहाल की जाए।

ऑपरेशन मुस्कान'' के तहत विगत जुलाई माह में विशेष टीम गठित कर अभियान चलाकर बालक/बालिकाओं को दस्तायब कर किया गया बरामद

जिले में ''ऑपरेशन मुस्कान'' के दौरान 15 गुमशुदा बालक एवं बालिका को दस्तयाब कर किया बरामद

ऑपरेशन मुस्कान'' के सफल संचालन हेतु जिले में विशेष टीम का किया गया गठन

तकनीकी सहायता के माध्यम से गुमशुदा बालक एवं बालिकाओं को राज्य एवं दीगर राज्यों में विशेष टीम भेज कर किया गया दस्तयाब

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार गुम बालक/बालिकाओं को खोजने हेतु ''ऑपरेशन मुस्कान'' के तहत एक माह में दिनांक 01.07.2025 से 31.07.2025 तक विशेष टीम गठित कर अभियान चलाकर 15 बालक/बालिकाओं को दस्तायब कर बरामद किया गया हैं। पुलिस महानिरीक्षक महोदय दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग (भा.पु.से.) एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू एवं डीएसपी श्रीमती संतोषी ग्रेस के मार्गदर्शन में जिले एवं थाना स्तर पर टीम गठित करते हुए तकनीकी सहायता के माध्यम से गुम बालक/बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु निरंतर प्रयास करते हुए 03 बालक एवं 12 बालिका कुल 15 बच्चों की पतासाजी कर दस्तयाब किया गया। ये बच्चे राज्य एवं दिगर राज्यों से बरामद किए गए। दर्ज एफआईआर में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। ''ऑपरेशन मुस्कान'' एक राज्यव्यापी अभियान है जो लापता बच्चों (बालक/बालिका) को खोजने और उन्हें बचाने के लिए गृह मंत्रालय की एक पहल है इसे ऑपरेशन स्माइल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक महीने तक चलने वाला अभियान होता है हालांकि यह अभियान लगातार जारी रहता हैं। इस अभियान के तहत राज्य पुलिस लापता बच्चो (बालक/बालिका) की पहचान करते है, उन्हें बचाते है उन्हें उनके परिवारों से जोड़ते है। बेमेतरा पुलिस ने लापता बालक/बालिकाओं (बच्चों) और उनके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लौटाने में सफलता हासिल की बरामद बालक/बालिकाओं (बच्चों) को उनके परिवारों को सौप दिया गया है। ''ऑपरेशन मुस्कान'' में विशेष टीम गठित किया गया। जिससे बेमेतरा ज़िले में विगत एक जुलाई माह में 15 गुमशुदा बालक/बालिकाओं की बरामदगी कर उनके परिवार को सुपुर्द किया गया एवं बालक/बालिकाओं के परिजनो ने अपने बच्चों को अपने पास पाकर बहुत खुश हुये और खुशी जाहिर करते हुए पुलिस विभाग का हृदय से अभार व्यक्त किये।

भाजपा सरकार ने मचाई है लुट आशीष छाबड़ा

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने बिजली उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल सीमा घटकर सिर्फ 100 यूनिट किए जाने को भाजपा सरकार की आम जनता की जेब में डाला गया डाका करार दिया है पूर्व विधायक आशीष शाहपुरा ने कहा कि अभी चंद दिनों पहले ही भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं के जेब में डाका डालकर बिजली यूनिट दरों को बढ़ाया था और चंद दिनों में ऐसी कौन सी आपदा आ गई जो बिजली उपभोक्ताओं को कांग्रेस सरकार के समय प्रारंभ की गई हाफ बिजली बिल योजना की सीमा घटकर सिर्फ 100 यूनिट तक के ही उपभोक्ताओं को हाफबिजली बिल छुठ स्कीम का लाभ दिए जाने की बात की जा रही है वास्तव में यह सब अदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के नियत से किया जा रहा है भाजपा सरकार जो लोगों के घरों में सोलर पैनल लगवाने की बात कर रही है वह सोलर पैनल अदानी ग्रुप के द्वारा ही बनाया जाता है और भाजपा सरकार अपने आका अदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए उसके द्वारा तैयार किए गए सोलर पैनल की बिक्री बढ़ाने के लिए आम जनता को बैंक से उधार दिलवाकर सोलर पैनल अपने घरों में लगवाने की स्कीम लाई है और इस लूट को भी मुक्त बिजली का नाम दिया जा रहा है जबकि इस बिजली के लिए उपभोक्ता को अपनी जेब से लाख रुपए से कम खर्च नहीं करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सोलर पैनल का विरोध करती है किंतु सिर्फ लोगों को मजबूर करके सोलर पैनल लगाने के लिए विवश करने का जो कार्य बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं उपभोक्ता को स्वतंत्र विकल्प होना चाहिए कि वह अपनी इच्छा से सोलर पैनल लगवाएं और सरकार को सोलर पैनल लगवाने का खर्च स्वयं वहन करना चाहिए आखिर आम उपभोक्ता जो अपने घर को बड़े मुश्किल से चला पा रहा है वह पहले से ही कर्ज में दबा हुआ है ऐसे में शासन द्वारा अघोषित तरीके से उसे पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि उपभोक्ता सोलर पैनल लगवाएं और यह सोलर पैनल या तो वह अपने जमा किए हुए पैसों को देखकर लगवाएं या बैंक से कर्ज लेकर लगवाएं जबकि होना यह चाहिए कि अगर भाजपा की नियत साफ है तो लोगों को मुक्त में सोलर पैनल लगाने के विकल्प दिए जाने चाहिए ना कि उनके नाम से बैंकों में कर्ज लेकर सोलर पैनल लगाने की योजना चलाई जानी चाहिए पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ की जनता अपनी आंखों से देख रही है कि किस तरीकों से भाजपा के द्वारा लोगों के घरों में डकैती की जा रही है आज आम जनता अपने को असहाय महसूस कर रही है ना तो भाजपा लोगों को शिक्षा दे पा रही है ना स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठा पा रही है और अब लोगों को बहाल करने के लिए लगातार बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने की जो साजिश कर रही है उसे जानता बुरी तरीके से परेशान हो चुकी है पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा आज 7 अगस्त गुरुवार दोपहर 12:30 बजे रोड स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भाजपा सरकार द्वारा हाफ बिजली बिल योजना 400 यूनिट को समाप्त करने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें उन्होंने आम जनता से तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में एकत्र होने की अपील की है पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा है कि यह अधिकार की लड़ाई है जिसमें सभी की भागीदारी अनिवार्य है।

26 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाला अंतर्राज्यीय ठग अनिल राय गिरफ्तार

जगदलपुर/मूक पत्रिका

कोतवाली पुलिस ने लगभग 26 करोड़ 36 लाख 74 हजार 904 रुपये की धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी अनिल राय को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी चार राज्यों ङ्क छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार व उत्तरप्रदेश में कुल 9 मामलों में वांछित था।

गिरफ्तार आरोपीः अनिल राय पिता राजदयाल राय, उम्र 43 वर्ष, निवासी फ्लैट नंबर 210, अपोलो डीवी सिटी, इंदौर, मध्यप्रदेश (स्थायी पताः चाणक्यपुरी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र)आरोपी (इंदौर/कोलकाता) व संचालक है।पिग आयरन खरीदी कर करोड़ों की रकम गबन करने का गंभीर आरोप।केस का प्रारंभःजगदलपुर निवासी मोहित चावड़ा ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी ने उनकी कंपनी से 209 टन पिग आयरन मंगाया जिसकी कीमत ?64,51,143 थी, परंतु भुगतान नहीं किया गया। आरोपी ने माल का पैसा हैदराबाद की कंपनी से लेकर उसे खुद की अन्य कंपनियों में उपयोग कर लिया और रकम हड़प ली।इसके बाद थाना कोतवाली जगदलपुर में अपराध क्रमांक 272/2025 धारा 318(4), 316(2), 3(5) मा.न्यासं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस की त्वरित कार्यवाहीःपुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में, एएसपी माहेश्वर नाग और सीएसपी अमित देवांगन के मार्गदर्शन में निरीक्षक भोला सिंह राजपूत के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से आईफोन-13 प्रो भी जब्त किया गया। तरीका वारदातःअनिल राय खुद को अपनी कंपनियों का डायरेक्टर बताकर, अलग-अलग कंपनियों से माल उठवाता और किसी अन्य को डिलीवर करवाकर पैसे वसूलकर गबन करता था। यह सिलसिला कई राज्यों में चला, और अब तक की विवेचना में 26 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का खुलासा हुआ है।

आयुष्मान अस्पताल के काउंटर अंदर दराज से नगदी रकम चोरी गए मामले में आरोपी को पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता

बेमेतरा/मूक पत्रिका

थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस टीम की कार्यवाही

जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू के निर्देशन में अपराध एवं अवैध गतिविधियों पर लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस टीम ने एक चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दे कि बीते 04 अगस्त 2025 को प्रार्थी विक्रम सिन्हा उम्र 20 साल साकिन पेन्ड्री तराई थाना बेमेतरा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 01 अगस्त 2025 के प्रातः 4::50 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति आयुष्मान अस्पताल के रिशेप्सन काउंटर अंदर के दराज में रखे नगदी 1,46,000/- रूपये को चोरी कर ले गया कि रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 331(4), 305(ए) ब्न्हस् के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार, अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह एवं एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा उप निरीक्षक मयंक मिश्रा व थाना स्टाफ को अज्ञात आरोपी की पता तलास हेतु त्वरित टीम गठित कर माल, मुल्जिम पता साजी में लगाया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए नयापारा बेमेतरा निवासी संदेही शेष मानस को हिरासत में लेकर पुछताछ की गई। पुछताछ करने पर पता चला कि 01 अगस्त 2025 को सुबह करीबन 4:00 बजे पैदल सिग्नल चौक की ओर जाना बाद आयुष्मान अस्पताल के अंदर कोई नही होने से दरवाजा खोलकर कांउटर के पास जाना जहा पर चाबी होने से चाबी लगाकर दराज को खोलकर अंदर रूपयों से भरा दो पैकेट होना दोनों पैकेट में कुल 1,46,000/- रूपये होना पैकेट को निकालकर रास्ता में फेंककर चोरी के रकम को अपने पास रखकर रायपुर जाना चोरी गये रकम में 43,000/- रूपये को जुआ खेलकर हार जाना और कुछ रकम को शराब में खर्च करना, चोरी का बचत रकम 1,03,000/- रूपये को घर में छुपा कर रखना।आरोपी के कब्जे से नगदी रकम 1,03,000/- रूपये (एक लाख तीन हजार रूपये) को जप्त कर बरामद किया गया आरोपी शेष मानस पिता बबलू मानस उम्र 35 साल साकिन वार्ड नं0 17 नयापारा बेमेतरा थाना बेमेतरा जिला बेमेतरा को बीते मंगलवार 05 अगस्त 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया। इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा उप निरीक्षक मयंक मिश्रा, सउनि मोहन लाल साहू, आरक्षक राहुल यादव, शिव सेन एवं अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण योगदान रहा।

देशी एवं अंग्रेजी शराब दुकान के आसपास अस्त व्यस्त व अनियंत्रित वाहनों के चलते किसी दिन हो सकती है बड़ी दुर्घटना जिम्मेदार कौन -- संतोष नाग आप नेता

- **शराबियों,मनचलों को नहीं रहा पुलिस प्रशासन का डर नशे में धूत होकर लड़खाते गन्दी गन्दी गाली गलौज व महिलाओं को कमेंट पास करते हुए गुजरते हैं सड़क मार्ग से -- नीरा ध्रुव**

केशकाल/मूक पत्रिका

पूर्व जनपद सदस्य नीरा ध्रुव के अगुवाई में दो वर्ष पूर्व शराब दुकान को हटाने के लिए जामगांव, कोदोभाट,ब्यालपुर, अड़ेगा, प्रधानचेरा, डोहलापारा बाडापारा ऐट्टेकोन्हाड़ी कच्छारपारा के माताएं बहने रैली प्रदर्शन कर चुकी हैं । केशकाल देशी एवं अंग्रेजी शराब दुकान तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय ,एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय तथा वन मंडल अधिकारी कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है । इस मार्ग से होकर आप केशकाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग विकास खंड तहसील क्षेत्र के गांवों का संपर्क जुड़ा हुआ है । इन सभी क्षेत्रों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, आई टी आई, एवं अन्य शासकीय कार्यालयों में सेवारत अधिकारी कर्मचारी सहित रोजमर्रा की जीवन से संबंधित कार्य के लिए भी बड़ी संख्या में इस सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं । चूंकि शराब दुकान सड़क मार्ग के ठीक सामने होने के कारण महिलाओं, बालिकाओं, तथा राहगीरों को सड़क मार्ग से गुजरते समय शराबियों, मनचलों, के गन्दी गाली गलौज, छेड़खानी का रोजाना सामना करना पड़ता है।

'सरल कार्यक्रम' के अंतर्गत बीजापुर में एक दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण सम्पन्न

- **प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु 7 जोनों में आयोजित हुआ प्रशिक्षण**

बीजापुर/मूक पत्रिका

जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में संचालित ÷सरल कार्यक्रम÷ के तहत दिनांक 6 अगस्त 2025 को बीजापुर ब्लॉक में जोन स्तर पर एक दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की भाषा और गणित विषयों में दक्षता को सुदृढ़ करना रहा। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को सरल कार्यक्रम की अवधारणा, इसकी आवश्यकता, महत्व, लक्ष्यों, टेस्टिंग टूल्स एवं शैक्षणिक गतिविधियों की समग्र जानकारी प्रदान की गई। बीजापुर ब्लॉक को इस आयोजन हेतु कुल सात जोनों में विभाजित किया गया, जहाँ प्रत्येक जोन में अलग-अलग केंद्रों पर प्रशिक्षण आयोजित हुआ। पूर्व में प्रशिक्षित कोर ग्रुप के सदस्यों ने इस बार मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षकों को कक्षा स्तर के अनुरूप बच्चों की शैक्षणिक स्थिति पहचानने और गतिविधि आधारित शिक्षण विधि अपनाने के लिए मार्गदर्शन दिया। पूरे प्रशिक्षण सत्र में शिक्षकों ने सरल कार्यक्रम की संरचना, शिक्षण तकनीकों और कक्षा में उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर गहन संवाद एवं अभ्यास किया। यह प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए सीखने का सशक्त माध्यम बना, साथ ही उनके अनुभवों और नवाचारों को साझा करने का एक मंच भी।इस प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग एबीईओ दीपक कोण्ड्रा, बीआरसी राजेश मिश्रा, सरल कार्यक्रम के जिला समन्वयक सागर दुर्गम तथा एससीटी विकास कुमार गुप्ता द्वारा की गई। सभी पर्यवेक्षकों ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं शिक्षकों की उत्साही भागीदारी की सराहना की।बीजापुर जिले में सरल कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में यह प्रशिक्षण एक मजबूत और सकारात्मक कदम सिद्ध हुआ है।

कांवड़ यात्रा का विधायक प्रतिनिधि अजय अग्रवाल ने विधायक ईश्वर साहू को खुमरी पहनकर किया भव्य स्वागत

बेमेतरा/देवकर/मूक पत्रिका

विधायक ईश्वर साहू के नेतृत्व में साजा नगर के महामाया मंदिर से प्राचीन शिव मंदिर सहसपुर तक 18 किलोमीटर कांवड़ यात्रा हुई पुरी.यात्रा बड़े ही धूमधाम से गाजे बाजे के साथ निकली।नगर भाजपा के लोग कांवड़ यात्रियों को पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया। रास्ते में पुष्प वर्षा, जलपान और स्वागत का विशेष प्रबंध नगर देवकर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा और जयघोष के साथ स्वागत किया। नगर देवकर के नौकेशा मार्ग में पेयजल व्यवस्था की गई थी, जिसमें भक्तों को गर्मी से राहत मिली । पुलिस विभाग ने सुरक्षा की पूरी कमान संभाली, वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी संतर्क रही । कांवड़ियों को तत्परता से प्राथमिक उपचार दिया गया। महिलाओं की विशेष टोली बनी आस्था की मिसाल, इस बार की यात्रा में 200 श्रध्दालु महिलाओं भी कांवड़ लेकर शामिल हुई।18 किलोमीटर की यह पदयात्रा महिलाओं की निष्ठा,शाक्ति और भक्ति का प्रतीक बनी।

इस अवसर पर जनपद पंचायत साजा उपाध्यक्ष एवं परपोडीं मंडल अध्यक्ष नारद वर्मा , पूर्व नगर पंचायत साजा अध्यक्ष हरिशंकर टावरी , किसान मोर्चा सदस्य मूलचंद शर्मा , वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रोशखर साहू, विधायक प्रतिनिधि अजय अग्रवाल,परपोडीं मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष सुश्री विनीता अग्रवाल दीदी, सेवा सहकारी समिति मर्यादित देवकर अध्यक्ष बुधारू साहू, पार्षद गण रविशंकर सोनी, सुरेश सिन्हा, माखन निषाद, देवेश गुप्ता ,धनी राम देवांगन, श्रीमती वर्षा साहू, श्रीमती पुष्पा साहू, श्रीमती सलमा बी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चिंता राम पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता मुन्नू चक्रधारी, भारतीय जनता पार्टी साजा विधानसभा मीडिया विभाग सह प्रभारी राकेश पाण्डेय, त्रिभुवन साहू, ब्रंद्री सिन्हा, गोल्डी साहू, संतोष निषाद ,अवध राम साहू, प्रवीण साहू,संजू साहू ,छकलू साहू जी, दिनेश यादव ,प्रेमी यादव जी ,दीपक सिन्हा , प्रकाश सोनी , लवकुश साहू,सौरभ सपहा, अर्जुन सिन्हा, नकुल सिन्हा, धमेंद्र पटेल , कल्लू सिन्हा, वरिष्ठ भाजपा नेता, पदाधिकारी गण कार्यकर्ता गण एवं उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ की नक्सल उन्मूलन नीति को मिली बड़ी सफलता

24 लाख के इनामी माओवादियों सहित 9 ने किया आत्मसमर्पण

बीजापुर/मूक पत्रिका

जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार को 24 लाख रुपये के इनामी 6 माओवादियों सहित कुल 9 माओवादियों ने सुरक्षाबलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में माड़ डिवीजन की कंपनी नंबर 1, प्लाटून नंबर 12 और 13 के,ष्टरू दक्षिण बस्तर डिवीजन की तकनीकी टीम, और धमतरी-गरियाबंद-नुआपाड़ा (ष्ठत्रह्) डिवीजन की चिन्नापल्ली एरिया कमेटी के सदस्य शामिल हैं। छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों का विवरण:1.बक्सू ओयाम (27 वर्ष, मुरिया, बोड़गा पटेलपारा, भैरमगढ़): माड़ डिवीजन कंपनी नंबर 1, पार्टी सदस्य, 8 लाख रुपये का इनाम, 2007 से सक्रिय।

2.बुधराम पोटाम (36 वर्ष, मुरिया, पुसनार, गंगालूर): प्लाटून नंबर 12,ष्टरू 5 लाख रुपये का इनाम, 2000 से सक्रिय।

3.हिड़मा उर्फ हिरिया (26 वर्ष, मुरिया, हिरमागुण्डा, गंगालूर): पश्चिम बस्तर डिवीजन प्लाटून नंबर 13,ष्टरू 5 लाख रुपये का इनाम, 2000 से सक्रिय।

4.मंगू उईका उर्फ टोग्गी (38 वर्ष, मल्लेपल्ली, बासागुड़ा): दक्षिण बस्तर डिवीजन तकनीकी टीम सदस्य, 2 लाख रुपये का इनाम, 2004 से सक्रिय।

5.रोशन कारम उर्फ सोनू उर्फ अजित (24 वर्ष, मुरिया, एड़समेटा, गंगालूर): ष्ठत्रह् डिवीजन चिन्नापल्ली एरिया कमेटी पार्टी सदस्य, 2 लाख रुपये का इनाम, 2010 से सक्रिय।

6.मंगलों पोड़ियाम (23 वर्ष, मुरिया, दरभा, कुटरू): भैरमगढ़ एरिया कमेटी पार्टी सदस्य, 2 लाख रुपये का इनाम, 2021 से सक्रिय।

7.कमलू हेमला उर्फ कुम्मा (28 वर्ष, मुरिया, फुलादी, मिरतुर): फुलादी ऋक्क्ष्ट छ्वस्रूस्- सदस्य, 2006 से सक्रिय।

8.बुधराम हेमला (47 वर्ष, मुरिया, फुलादी, मिरतुर): फुलादी ऋक्क्ष्ट छ्वस्रूस्- सदस्य, 2014 से सक्रिय।

9.पण्डरू पूनेम उर्फ पदखूटा (38 वर्ष, मुरिया, मनकेली, गंगालूर): मनकेली भूमकाल मिलिशिया कमांडर, 1997 से सक्रिय।

आत्मसमर्पण का कारण

आत्मसमर्पण के पीछे छत्तीसगढ़ शासन की नियद नेल्ला नार योजना और नक्सल उन्मूलन नीति का प्रभाव प्रमुख है। सुदूर क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तार, सामुदायिक पुलिसिंग, और सुरक्षाबलों के सकारात्मक संवाद ने माओवादियों का संगठन से मोहभंग कराया है। संगठन के भीतर आंतरिक मतभेद, शोषण, और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की चाह ने उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया।

नक्सल विरोधी अभियान की सफलता

1 जनवरी 2025 से अब तक बीजापुर जिले में 310 माओवादी गिरफ्तार किए गए, 277 ने आत्मसमर्पण किया, और विभिन्न मुठभेड़ों में 131 माओवादी मारे गए। 2024 से अब तक 1013 माओवादी गिरफ्तार, 466 ने आत्मसमर्पण किया, और 189 मुठभेड़ में मारे गए। ष्ठक्रत्र, स्ञ्जस्न, ष्टक्रक्कस्न, कोबरा, और बस्तर फाइटर्स के संयुक्त अभियानों ने माओवादी गतिविधियों को कमजोर किया है।

आत्मसमर्पण समारोह

आत्मसमर्पण समारोह में उप पुलिस महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप, उप महानिरीक्षक ष्टक्रक्कस्न सेक्टर बीजापुर बी.एस. नेगी, पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेंद्र कुमार यादव, और विभिन्न ष्टक्रक्कस्न बटालियनों के कमांडेंट्स मौजूद थे। आत्मसमर्पित माओवादियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया।

पुलिस अधीक्षक की अपील

पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने माओवादियों से आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा, ÷छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति आत्मसमर्पित माओवादियों को रोजगार, शिक्षा, और सम्मानजनक जीवन का अवसर देती है।÷ उन्होंने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और विकास की राह अपनाने का आह्वान किया।

भविष्य की संभावनाएं

नक्सल विरोधी अभियानों और पुनर्वास नीति के चलते माओवादी संगठन कमजोर हुआ है। खुफिया सूचनाओं के अनुसार, आने वाले समय में और माओवादी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। सरकार की नियद नेल्ला नार योजना और सुरक्षा बलों की सक्रियता ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास की उम्मीद जगाई है।

संपादकीय

ट्रंप की दादागिरी के आगे न झुके सरकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अचानक से भारत को लेकर बेहद आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने भारत पर 25त्न टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और यह भी चेताया है कि रूस से व्यापार की एवज में कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाया जाएगा। ट्रंप के इस फैसले का क्या असर पड़ सकता है, इस बारे में सरकार आकलन कर रही है। बातचीत के रास्ते खुले हैं और वह होनी भी चाहिए, लेकिन इस मामले में भारत को अपने हितों को भी मजबूती से रखना होगा।ट्रंप का हालिया बयान केवल टैरिफ या व्यापार घाटे से नहीं जुड़ा। इसके पीछे लंबी हताशा और अपनी इमेज बचाने की चिंता है। कई चरण की बातचीत के बावजूद दोनों देशों की ट्रेड डील किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। रोड़ा अटका हुआ है कृषि और डेयरी सेक्टर पर। हर डील अपनी शर्तों पर करने वाले ट्रंप इन दोनों सेक्टर में अमेरिका के लिए खुली छूट चाहते हैं। ऐसा करना भारतीय किसानों के हित में नहीं होगा और सरकार को इस मामले में बिल्कुल भी नहीं झुकना चाहिए। व्यापार एकतरफा फायदे को देखकर नहीं किया जा सकता। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत के साथ असहमति की जो वजहें गिनाई हैं, उसमें रूस से तेल खरीदना प्रमुख है। 2022 तक भारत की तेल आपूर्ति में रूस का हिस्सा सिर्फ 1 प्रतिशत था। आज यह आंकड़ा 35-40प्रतिशत है, और जरूरत पड़ने पर इससे पीछे हटना संभव है, क्योंकि अब रूसी तेल पर पहले जितना फायदा नहीं हो रहा। लेकिन, यहां बात केवल फायदे नहीं, दो देशों के रिश्तों और हक की भी है। भारत की अपनी ऊर्जा जरूरतें हैं। आखिर अमेरिका ने भी तो उस पाकिस्तान के साथ डील की, जो वैश्विक मंचों पर कई बार आतंकवाद की शरणस्थली साबित हो चुका है।ट्रंप न अपने बयानों पर स्थिर रहते हैं और न पॉलिसी पर। जिन देशों ने उनके साथ डील की है, उन्हें भी कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रिटेन, वियतनाम से डील के बावजूद टैरिफ बढ़ रहा है। इसी तरह, ईयू के कई देश नाराज हैं क्योंकि आयात शुल्क औसत 4.8प्रतिशत से बढ़कर अब 15प्रतिशत हो चुका है। यानी किसी भी सूरत में टैरिफ की स्थिति पहले वाली नहीं रहेगी। इसलिए भारत को किसी दबाव में नहीं आना चाहिए।रुबियो ने भारत को अमेरिका का सहयोगी और रणनीतिक भागीदार बताया है। उनके देश को चीन का सामना करने के लिए भारत जैसे सहयोगी की दरकार है। लेकिन, उनका बर्ताव एक दोस्त जैसा नहीं है। भारत को अगर कुछ मामलों में अमेरिका की जरूरत है, तो अमेरिका को भी कई जगह भारत का साथ चाहिए।

29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम विस्फोट की न्यायिक परिणति ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि कैसे सत्ता, वोटबैंक और वैचारिक पूर्वाग्रहों ने भारतीय न्याय और निष्पक्षता की नींव को झकझोर दिया। मुंबई की एनआईए कोर्ट द्वारा सातों आरोपियों-प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित को सबूतों के अभाव में बरी कर देना न केवल कानूनी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण फैसला है, बल्कि यह उस भगवा आतंकवाद की मिथ्या कथा पर भी करारा प्रहार है जिसे वर्षों तक कांग्रेस ने राजनीतिक मंचों और मीडिया के जरिए प्रचारित किया गया। यह कांग्रेस की फर्जी कहानी का अंत एवं सत्य की जीत का एक अमूल्य आलेख है।

मालेगांव विस्फोट एवं भगवा पर कलंक की साजिश

(ललित गर्ग)

- भगवा आतंकवाद शब्द का पहली बार प्रयोग उस समय के कुछ कांग्रेसी नेताओं ने किया, जिनका उद्देश्य स्पष्ट था, वोटबैंक की तुष्टिकरण नीति, मुस्लिम समाज को डराकर एकतरफा ध्रूवीकरण और हिंदू संगठन व सनातन मूल्यों को कलंकित करना।
- 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम विस्फोट की न्यायिक परिणति ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि कैसे सत्ता, वोटबैंक और वैचारिक पूर्वाग्रहों ने भारतीय न्याय और निष्पक्षता की नींव को झकझोर दिया। मुंबई की एनआईए कोर्ट द्वारा सातों आरोपियों-प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित को सबूतों के अभाव में बरी कर देना न केवल कानूनी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण फैसला है, बल्कि यह उस भगवा आतंकवाद की मिथ्या कथा पर भी करारा प्रहार है जिसे वर्षों तक कांग्रेस ने राजनीतिक मंचों और मीडिया के जरिए प्रचारित किया गया। यह कांग्रेस की फर्जी कहानी का अंत एवं सत्य की जीत का एक अमूल्य आलेख है।
- अदालत का यह वक्तव्य कि 'आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता', भारतीय संस्कृति और न्यायशास्त्र की मूल आत्मा को पुनः जीवित करता है। यह वही भारत है जहां 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' और 'अहिंसा परमो धर्मः' की गूंज होती रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश 2008 के बाद हिंदू धर्म, हिंदुत्व और भगवा पर ऐसा कलंक मढ़ा गया मानो वे आतंकवाद के स्रोत हों। मालेगांव विस्फोट मामले में एनआइए की विशेष अदालत उस नतीजे पर पहुंची, जिस पर बांबे हाई कोर्ट ट्रेन विस्फोट कांड की सुनवाई करते हुए पहुंचा था। ऐसा कई आतंकी घटनाओं के मामलों में हो चुका है। इससे यही पता चलता है कि कभी जांच एजेंसियां, कभी अदालतें और कभी दोनों अपना काम सही तरह और समय पर नहीं करतीं। जांच और फिर अदालती कार्यवाही में देरी तथा ढिलाई एक बड़ा रोग है। आतंक के मामलों की जांच में यह भी कोई दबी-छिपी बात नहीं कि संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ, मुस्लिम तुष्टिकरण एवं वोट बैंक बाधा बनते हैं। आतंकी घटनाओं को राजनीतिक रंग दिया जाता है। मालेगांव विस्फोट कांड में प्रज्ञा ठाकुर, सुधाकर द्विवेदी आदि की गिरफ्तारी के आधार पर हिंदू और भगवा आतंक का जुमला उछाला गया। इसका मकसद कथित भगवा आतंक को जिहादी आतंक जैसा बताना था। यह हिंदू ही नहीं, देश विरोधी साजिश थी। इसका लाभ पाकिस्तान को मिला, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं ने समझौता एक्सप्रेस कांड पर भी एजेंसियों के सहारे भगवा आतंक की फर्जी कहानी गढ़ी।

भगवा आतंकवाद शब्द का पहली बार प्रयोग उस समय के कुछ कांग्रेसी नेताओं ने किया, जिनका उद्देश्य स्पष्ट था, वोटबैंक की तुष्टिकरण नीति, मुस्लिम समाज को डराकर एकतरफा ध्रूवीकरण और हिंदू संगठन व सनातन मूल्यों को कलंकित करना। इसका परिणाम हुआ कि वर्षों तक निर्दोष लोग जेल में सड़ते रहे। साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकुर को एक संन्यासी जीवन से घसीट कर हिरासत में लिया गया, प्रताड़ित किया गया और उनके आध्यात्मिक जीवन को ध्वस्त कर दिया गया। सवाल यह है कि जब सबूत नहीं थे, तब उन्हें जेल में रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों जांच एजेंसियों ने बेसिर-पैर की कहानियों को सच मान लिया? क्यों मीडिया ने बिना परीक्षण के 'हिंदू आतंकवाद' की ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी? यह वही मानसिकता थी जो आतंकवाद को धर्म से जोड़कर एक खास समुदाय को डराने और एक संप्रदाय को बदनाम करने में लगी थी। यह कांग्रेस का एक षडयंत्र एवं साजिश थी जो अब पर्दापाश हो गयी है। कांग्रेस शासित प्रांत में सत्ता का जमकर दुरुपयोग किया गया।

मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गई थी। धमाके में 100 से अधिक घायल हुए थे। न्यायाधीश ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि मामले को संदेह से परे साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं है। मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधान लागू नहीं होते। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह साबित नहीं हुआ है कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर पंजीकृत थी, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया है। यह भी साबित नहीं हुआ है कि विस्फोट कथित तौर पर बाइक पर लगाए गए बम से हुआ था। कोर्ट ने कहा, श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के आवास में विस्फोटकों के भंडारण या संयोजन का कोई सबूत नहीं मिला। अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि विस्फोट से ठीक पहले वह साध्वी प्रज्ञा के पास थी।

इससे पहले सुबह सातों आरोपी दक्षिण मुंबई स्थित सत्र न्यायालय पहुंचे, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। आरोपी जमानत पर बाहर थे। मामले के आरोपियों में प्रज्ञा ठाकुर, पुरोहित, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। उन सभी पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता तथा शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आतंकवादी कृत्य करने का आरोप लगाया गया था। इस पूरे प्रकरण में न्यायपालिका की देरी और जांच एजेंसियों की लापरवाही स्वयं अदालत द्वारा उजागर की गई। अदालत ने कहा कि ना तो घटनास्थल का स्केच बनाया गया, ना फिंगरप्रिंट लिए गए, ना बम के सटीक स्रोत की पुष्टि हुई और ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष प्रमाण था। अभियोजन पक्ष ने जिस मोटरसाइकिल को बम के लिए इस्तेमाल होने की बात कही थी, वह भी प्रज्ञा ठाकुर से जुड़ी नहीं पाई गई। यह सब कुछ बताता है कि पूरा केस पूर्वग्रहों, दुर्भावना और राजनीतिक साजिश से प्रेरित था। यदि न्याय के नाम पर निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया जाए, तो वह केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि समस्त समाज और संस्कृति को दंडित करने जैसा होता है। प्रश्न यह उठता है-तो क्या अब तक इन आरोपियों को गलत तरीके से आतंकवादी घोषित कर वर्षों तक सलाखों के पीछे रखा गया?

हिंदू धर्म और आतंकवाद-ये दो शब्द आपस में मेल नहीं खाते। सनातन संस्कृति का मूल आधार ही शांति, सहिष्णुता और करुणा है। विश्व में यदि कोई धर्म ऐसा है जिसने 'युद्ध नहीं, यज्ञ', 'हिंसा नहीं, अहिंसा' का मार्ग दिखाया है, तो वह हिंदू धर्म है। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, विवेकानंद और गांधी-इन सभी की परंपरा में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं। 'भगवा आतंकवाद' एक गढ़ा गया मिथक था, जो ना केवल हिंदू समाज को कलंकित करता है, बल्कि भारत की आत्मा को भी चोट पहुंचाता है। भगवा वस्त्र तो त्याग, तपस्या और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। उसे बम और खून से जोड़ना स्वयं भारतीयता के खिलाफ साजिश है।

इस फैसले ने जहां एक ओर निर्दोषों को न्याय दिया, वहीं दूसरी ओर यह देश के जनमानस को आत्ममंथन का अवसर भी देता है, क्या हम इतनी आसानी से किसी को भी आतंकवादी घोषित कर देंगे? क्या हम किसी राजनीतिक विचारधारा के विरोध के कारण पूरे धर्म को कटघरे में खड़ा कर देंगे? क्या धर्म का दुरुपयोग कर वोटबैंक की राजनीति करते रहेंगे? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की प्रतिक्रिया-आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है इस बयान में उनके दर्द एवं यथार्थ को समझने की आवश्यकता है। यह केवल एक साध्वी की व्यक्तिगत मुक्ति की खुशी नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की आवाज़ है जिनके लिए भगवा आस्था और अस्मिता का प्रतीक है।

वर्षों तक मीडिया ने इस मामले को सनसनीखेज बनाकर 'हिंदू आतंकवाद' को ग्लैमराइज किया। प्राइम टाइम पर भगवा को हिंसा से जोड़ना, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 'संदिग्ध आतंकी' की तरह चित्रित करना और बिना न्यायिक पुष्टि के चरित्रहनन करना, पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ था। वहीं, तथाकथित बुद्धिजीवियों एवं देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले में एकतरफा विचारधारा के चलते भगवा को 'खतरा' घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे लोगों से अब यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे?

मालेगांव विस्फोट मामले में आया फैसला केवल न्यायिक विजय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। यह भारत की न्याय प्रणाली, समाज की सहिष्णुता और धर्म की शुद्धता का प्रमाण है। आज समय है, जब राष्ट्र को यह समझना चाहिए कि धर्म को आतंक से जोड़ना स्वयं एक मानसिक आतंक है। सत्य को स्वीकारने का साहस कीजिए, क्योंकि न्याय तभी पूर्ण होता है जब उसमें निष्पक्षता, संवेदना और सत्य का साथ हो। यह मामला दर्शाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पस्त या पराजित नहीं। सत्यमेव जयते- यह सत्य की जीत है, सनातन की जीत है। भगवा वस्त्रों पर लगे झूठे दाग अब धुल चुके हैं, अब समय है संस्कृति के गौरव को फिर से स्थापित करने का। लेखक, पत्रकार, स्तंभकार हैं। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

आत्मघाती साबित हो सकता है ट्रंप का टैरिफ

(डा. रवीन्द्र अरजरिया)

अमेरिका अपने स्लीपर सेल की दम पर समूची दुनिया में सरकारें बदलने का षडयंत्र लम्बे समय से करता आ रहा है। बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका तक, कनाडा से लेकर स्कॉटलैंड तक और मेक्सिको से लेकर यूक्रेन तक अमेरिका ने हमेशा ही सरकार गठन के दौरान हस्तक्षेप किया है। वह विदेशों में वहां के मीरजाफरों की फौज एकत्रित करता है, उन्हें पैसों की चमक दिखाता है और फिर सरकार विरोधी दलों के साथ सांठगांठ करके अपने षडयंत्र की अमली जामा पहनाने में जुट जाता है। बांग्लादेश इसका जीता जागता उदाहरण है जहां उसने एक विशेष भू भाग हथियाने का प्रयास किया जिसमें सफल न होने पर वहां के सरकार विरोधियों के सहयोग से अपने पसन्दीदा व्यक्ति को सिंहासन पर बैठा दिया। यूक्रेन पर दबाव बनाकर अपने इच्छित समझौते पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ही घर में कर चुके हैं। अब भारत की बढती अर्थव्यवस्था और एक विशाल बाजार देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति नित नये फरमान जारी करके दबाव बनाने की जी तोड कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत सम्मानित है। विगत चार सालों में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6 प्रतिशत से अधिक ही रही है। वर्ष 2023 में यह आंकडा 9.2त्न तक जा पहुंच गया था। जबकि अमेरिका की अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ष 2022 से 2025 के मध्य मात्र 3 प्रतिशत से ऊपर ही नहीं गई। अमेरिका की कुल आबादी से लगभग दो गुना लोग तो भारत में केवल नौकरीपेशा ही है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5त्न की दर से बढ़ सकती है जो कि एक उपलब्धि होगी। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारतीय अर्थ व्यवस्था को डेड इकनॉमी बताकर अपनी षडयंत्रकारी प्रवृत्ति का स्वयं ही खुलासा कर दिया है। भारत के संसदीय सत्र के दौरान ट्रंप ने बयान दिया जिसके आधार पर नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी ने तत्काल सरकार को घेरने की अपनी नाकाम कोशिश शुरू कर दी। यह अगल बात है कि उन्हें उनकी ही पार्टी के नेताओं ने ही आइना दिखा दिया। टैरिफ की गीदड़ भभकी देने वाले ट्रंप ने 7 अगस्त से अपना फरमान लागू करने की घोषणा कर दी है जिससे 69 देशों सहित पूरा यूरोपीय संघ सीधा प्रभावित हो रहा है। टैरिफ के अनुसार अफगानिस्तान पर 15, एलजीरिया पर 30 प्रतिशत, अंगोला पर 15 प्रतिशत, बांग्लादेश पर 20, बोलीविया पर 15, बोस्निया पर 30, हर्जेगोविना पर 30, बोत्सवाना पर 15, ब्राजिल पर 10, ब्रुनेई पर 25, कंबोडिया पर 19, कैमरून पर 15, कोस्टा रिका पर 15, कोटे डी आइवर पर 15, कांगो 15, इक्वेडोर पर 15, इक्वेटोरियल गिनी पर 15, यूरोपीय संघ पर 15, फाकलैंड द्वीप समूह पर 10, फिजी पर 15, घाना पर 15, गुयाना पर 15, आइसलैंड पर 15, भारत पर 25, इंडोनेशिया पर 19, इराक पर 35, इजराइल पर 15, जापान पर 15, जॉर्डन पर 15, कजाखस्तान पर 25, लाओस पर 40, लिसोटो पर 15, लीबिया पर 30, लिकटेंस्टाइन पर 15, मेडागास्कर पर 15, मलावी पर 15, मलेशिया पर 19, मॉरीशस पर 15, मोलदोवा पर 25, मोजाम्बिक पर 15, म्यांमार यानी बर्मा पर 40, नामिबिया पर 15, नाउरू पर 15, न्यूजीलैंड पर 15, निकारागुआ पर 18, नाइजीरिया पर 15, उत्तर मैसेडोनिया पर 15, नॉर्वे पर 15, पाकिस्तान पर 19, पापुआ न्यू गिनी पर 15, फिलिपींस पर 19, सर्बिया पर 35, दक्षिण अफ्रीका पर 30, दक्षिण कोरिया पर 15, श्रीलंका पर 20, स्विट्जरलैंड पर 39, सीरिया पर 41, ताइवान पर 20, थाईलैंड पर 19, त्रिनिदाद पर 15, टोबैगो पर 15, ट्यूनीशिया पर 25, टर्की पर 15, युगांडा पर 15, यूनाइटेड किंगडम पर 10, वानुअतु पर 15, वेनेजएला पर 15, वियतनाम 20, जाम्बिया पर 15 तथा जिम्बाब्वे पर 15 प्रतिशत टैरिफ देना होगा। सबसे ज्यादा टैक्स रेट वाले देशों में सीरिया को 41, स्विट्जरलैंड को 39, लाओस और म्यांमार को 40, इराक और सर्बिया को 35 और लीबिया और अल्जीरिया को 30 प्रतिशत की सीमा में रखा गया हैं जबकि ताइवान, भारत और वियतनाम जैसे अन्य देश 20 से 25 प्रतिशत की सीमा में हैं। इस सबके पीछे भारत का वैश्विक मंच पर बढता कद, स्वदेशी उत्पादन की वृद्धि, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का बढता ग्राफ, ब्रिक्स करैन्सी की योजना, रूस के साथ गहरे संबंध, चीन के साथ कायम होता संतुलन, मालदीप जैसे देशों का पुनः जागता भारत प्रेम जैसे अनेक कारण हैं जिनके कारण डोनाल्ड ट्रंप अपनी गिरती साख को बचाने के लिए मुहम्मद तुगलक बनकर एक पागल बादशाह का पर्याय बनते जा रहे हैं। अमेरिका ने पहली बार भारत पर षडयंत्र शस्त्र से आक्रमण नहीं किया है बल्कि इतिहास के पन्नों में उसकी घातक मानसिकता के संदर्भ भरे पडे हैं। सन् 1962 में भारत-चीन युद्ध होने के कारण देश के हालत चिन्ताजनक हो गये थे। उसके बाद सन् 1965 में भारत को पाकिस्तान से युद्ध करना पड गया। तब अमेरिका से आने वाले अनाज पर ही देश पूरी तरह निर्भर था। ऐसे में युद्ध के मध्य ही अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बेन्स जॉनसन ने भारत को अनाज देने से मना कर दिया था। उसका मानना था कि भारतवासी अब अमेरिका के सामने घुटना टेककर आत्मसमर्पण कर देंगें मगर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने अपने नागरिकों के साथ मिलकर हरित क्रांति शंखनाद करके अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। इसी तरह सन् 1998 में परमाणु परीक्षण के दौरान भी अमेरिका ने भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया किन्तु देश एक बार फिर अपने आत्मविश्वास की दम पर सीना ताने खडा रहा। आज देश में मिसाइलों से लेकर फाइटर जेट तक, कम्प्यूटर से लेकर मोबाइल फोन तक, अत्याधुनिक मशीनरीज से लेकर भारी संयत्रों तक का निर्माण हो रहा है। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र की गहराइयों तक में भारत का डंका बज रहा है। ऐसे में दबाव की राजनीति, दमन का षडयंत्र और पीठ में छुरा भौंकने में माहिर अमेरिका अपनी खोखली धमकियों और देश में स्लीपर सेल के रूप में छुपे मीर जाफरों की दम पर भारत को एक बार फिर झुकाने का मंसूबा पाल बैठा है जो आने वाले समय में आत्मघाती कदम हो सकता है।

राजनीति में भद्रता की मिसाल थे अरुण जेटली, उन पर धमकाने का आरोप लगाना घटिया राजनीति है

खुद कई मामलों में जमानत पर चल रहे राहुल गांधी की सारी राजनीति आरोप लगाते रहने पर ही टिकी हुई है। वह भारत में बोलें या विदेशी धरती पर, उनके संबोधनों में सिर्फ भारत की सरकार और भारत के संवैधानिक संस्थान ही निशाने पर होते हैं। राहुल गांधी पहले प्रधानमंत्री के लिए 'चौकीदार चोर है' वाली टिप्पणी का उपयोग करते थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई तो वह संवैधानिक संस्थानों को चोर बताने लग गये हैं। एक दिन पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाते हुए कहा था कि रिटायर हो जाओगे तब भी तुम्हें ढूँढ़ निकालेंगे और आज उन्होंने उन लोगों पर हमले शुरू कर दिये जोकि इस धरा पर अपना पक्ष रखने के लिए नहीं हैं।

(नीरज कुमार दुबे)

- राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता तो पलटवार कर ही रहे हैं साथ ही स्वर्गीय अरुण जेटली के पुत्र रोहन जेटली ने भी राहुल गांधी के बयान को तथ्यात्मक रूप से गलत और दिवंगत नेता की स्मृति के प्रति अनादरपूर्ण बताया है।
- खुद कई मामलों में जमानत पर चल रहे राहुल गांधी की सारी राजनीति आरोप लगाते रहने पर ही टिकी हुई है। वह भारत में बोलें या विदेशी धरती पर, उनके संबोधनों में सिर्फ भारत की सरकार और भारत के संवैधानिक संस्थान ही निशाने पर होते हैं। राहुल गांधी पहले प्रधानमंत्री के लिए 'चौकीदार चोर है' वाली टिप्पणी का उपयोग करते थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई तो वह संवैधानिक संस्थानों को चोर बताने लग गये हैं। एक दिन पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाते हुए कहा था कि रिटायर हो जाओगे तब भी तुम्हें ढूँढ़ निकालेंगे और आज उन्होंने उन लोगों पर हमले शुरू कर दिये जोकि इस धरा पर अपना पक्ष रखने के लिए नहीं हैं।
- राहुल गांधी ने स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली पर जो आरोप लगाये हैं वह बेहद निचले स्तर की राजनीति है। राहुल गांधी अमीर घराने से जरूर हैं लेकिन सभ्यता के मामले में बेहद गरीब हैं क्योंकि वह यह सामान्य-सी बात भी नहीं जानते कि हमारे धर्म और संस्कृति में यही सिखाया जाता है कि स्वर्गीय व्यक्ति के प्रति कभी भी अनादर नहीं प्रकट करना चाहिए। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि अरुण जेटली ने उन्हें धमकाया जबकि असलियत यह है कि स्वर्गीय अरुण जेटली जनवरी 2019 से ही एक तरह से बिस्तर पर थे। हम आपको याद दिला दें कि फरवरी 2019 में जब जेटली को बतौर वित्त मंत्री लोकसभा चुनावों से पहले संसद में अंतरिम बजट पेश करना था तब उनकी अमेरिका में सर्जरी होने की

वजह से उनकी जगह वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। उसके बाद जेटली की जगह पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था।

- हम आपको यह भी बता दें कि अरुण जेटली की 14 मई 2018 को किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी हुई थी और उसके बाद से वह घर से ही काम कर रहे थे। वह अपने मंत्रालय की बैठकों में भी ऑनलाइन शामिल होते थे और अत्यंत आवश्यक होने पर ही लोगों से मुलाकात करते थे क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें किसी से मिलने से मना किया हुआ था। ऐसे में राहुल गांधी का यह दावा कि अरुण जेटली उन्हें धमकाने गये थे ना सिर्फ सफेद झूठ है बल्कि देश के ईमानदार नेताओं में शुमार रहे व्यक्ति की छवि पर प्रहार भी है। देखा जाये तो राहुल गांधी कहने को तो कांग्रेस के लीगल कॉन्कलेव में बोल रहे थे लेकिन यहां बातें उन्होंने इल-लीगल कह दीं।
- दूसरी ओर, राहुल के बयान पर भाजपा नेता तो पलटवार कर ही रहे हैं साथ ही स्वर्गीय अरुण जेटली के पुत्र रोहन जेटली ने भी राहुल गांधी के बयान को तथ्यात्मक रूप से गलत और दिवंगत नेता की स्मृति के प्रति अनादरपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा, मेरे पिता का 2019 में निधन हो गया था, जबकि कृषि कानून 2020 में पेश किए गए थे। राहुल गांधी का यह दावा समय-सीमा के हिसाब से असंभव है। रोहन ने यह भी कहा कि अरुण जेटली लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते थे और कभी भी दबाव की राजनीति नहीं करते थे। रोहन ने कहा कि वह संवाद और सहमति निर्माण में विश्वास रखते थे। यदि कोई राजनीतिक मतभेद होता भी, तो वे खुली और रचनात्मक चर्चा के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास करते थे। उन्होंने राहुल गांधी को चेतावनी दी कि दिवंगत नेताओं को राजनीतिक विवादों में न घसीटें। रोहन जेटली ने कहा कि राहुल गांधी ने मनोहर परिकर जी के मामले में भी कुछ ऐसा ही किया था। कृपया डिपेर्ड लीडर को शांति से रहने दें।
- इस बीच, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने - पर लिखा, राहुल गांधी के झूठ अब बर्दाश्त से बाहर हैं। वह बार-बार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का नाम अपनी कल्पनाओं से भरे बयानों में घसीटते हैं। यह दावा कि अरुण जेटली जी ने उन्हें कृषि कानूनों पर धमकाया, न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि पूरी तरह से शर्मनाक और घृणित है। प्रमोद सावंत ने यह भी याद दिलाया कि राहुल गांधी ने स्वर्गीय मनोहर परिकर के मामले में भी गलत बयान दिए थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने राफेल सौदे पर झूठा आरोप लगाने के लिए परिकर जी से मुलाकात का गलत अर्थ प्रस्तुत किया था। ऐसे बयान न केवल तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं, बल्कि उन नेताओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया।
- बहरहाल, देखा जाये तो राहुल गांधी की यह आदत बन गयी है कि वह राजनीतिक लाभ के लिए दिवंगत नेताओं के नाम और छवि का इस्तेमाल करते हैं। यह न केवल राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ है बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अनुचित है। साथ ही ऐसे बयानों से न केवल राजनीतिक विमर्श का स्तर गिरता है, बल्कि दिवंगत नेताओं की छवि भी अनावश्यक रूप से विवादों में घसीटी जाती है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे तथ्यों के साथ अपनी दलीलें रखें और व्यक्तिगत या मृत नेताओं पर हमले करने से बचें।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

केन्द्रीय विद्यालय बेमेतरा के संचालन की तैयारियाँ अंतिम चरण में, कलेक्टर रणबीर शर्मा ने किया स्थल निरीक्षण एवं प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा

विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक संसाधनों की सूची भी की गई संलग्न, जल्द प्रारंभ होगा नया शिक्षा सत्र

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले के शैक्षणिक परिदृश्य को एक नई ऊंचाई देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए बीते बुधवार को कलेक्टर रणबीर शर्मा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर बावामोहतरा का निरीक्षण किया।आगामी शिक्षा सत्र 2025-26 से केन्द्रीय विद्यालय बेमेतरा का संचालन प्रारंभ किया जाना है। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यालय संचालन की तैयारियों की समीक्षा करना एवं कक्षा पहली से पाँचवीं तक के लिए प्राप्त प्रवेश आवेदनों की अंतिम दिन की स्थिति का मूल्यांकन करना था। इस दौरान एडीएम अनिल वाजपेयी, अपर कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज, डीईओ कमल बंजारे, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य गण, एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे 7 निरीक्षण के दौरान कलेक्टर शर्मा ने विद्यालय प्रबंधन से विस्तारपूर्वक चर्चा की और सभी प्राप्त आवेदन पत्रों का अवलोकन किया। उन्होंने प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए प्रचार्यों को निर्देशित किया कि प्रत्येक अभिभावक और विद्यार्थी को समय पर तथा स्पष्ट सूचना प्रदान की जाए। इस संबंध में उन्होंने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया की अनंतिम चयन सूची आगामी 11 अगस्त 2025, सोमवार को जारी की जाएगी, जिसे विद्यालय के नोटिस बोर्ड अथवा अन्य उपयुक्त माध्यमों से सार्वजनिक किया जाएगा। कलेक्टर शर्मा ने निर्देशित किया कि विद्यालय संचालन की दिशा में कोई भी कार्य लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक तौर पर कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं का संचालन किया जाएगा, और भविष्य में छात्र संख्या एवं संसाधनों के अनुसार इसका विस्तार किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विद्यालय के सुचारूपूर्वक संचालन हेतु आवश्यक संसाधनों एवं सामग्रियों की सूची संलग्न की गई है, जिसे प्राथमिकता से पूर्ण किया जाना आवश्यक है। इसी बीच निरीक्षण के दौरान कलेक्टर रणबीर शर्मा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बावामोहतरा के छात्रों से भी संवाद किया। उन्होंने बच्चों से विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे और सही उत्तर देने वाले छात्रों को मिठाई वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने शिक्षकों को निर्देशित किया कि बच्चों की जिज्ञासा एवं ज्ञानवर्धन के लिए रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन नियमित रूप से किया जाए। कलेक्टर ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षा सत्र की शीघ्र शुरुआत सुनिश्चित की जाए, जिससे जिले के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विद्यालय के प्रारंभ से न केवल बेमेतरा बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी बेहतर शैक्षणिक अवसर प्राप्त होंगे। अभिभावक अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए कार्यदिवसों में विद्यालय के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यह एक सुनहरा अवसर है कि बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान में अध्ययन का अवसर प्राप्त हो रहा है, अतः सभी संबंधित अभिभावकों से अपेक्षा है कि वे विद्यालय की सूचनाओं पर नियमित रूप से ध्यान दें।

पण्डो जनजाति की जमीन पर गैर, आदिवासी का कब्जा, प्रशासनिक मिलीभगत का आरोप

नरेंद्र यादव ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, चेताया, जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तय

सूरजपुर/मूक पत्रिका

जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति पण्डो समुदाय की जमीन पर गैर-आदिवासी परिवार द्वारा कब्जा और अवैध नामांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिला पंचायत सदस्य एवं युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव ने मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन में ज्ञापन सौंपते हुए इस गंभीर मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में लटोरी तहसील अंतर्गत भगवानपुर कला के खसरा क्रमांक 43, रकबा 1.71 हेक्टेयर (पुराना खसरा नं. 5 से 12) की भूमि का उल्लेख है, जो पूर्व में पण्डो जनजाति के झुरई पण्डो के नाम दर्ज थी। आरोप है कि इस भूमि का अवैध रूप से नामांतरण कर इसे एक गैर-आदिवासी बंगाली परिवार के नाम पर दर्ज कर दिया गया है, जिसमें हल्का पटवारी की संलिप्तता बताई गई है। यह नामांतरण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके तहत आदिवासी भूमि का गैर-आदिवासी को हस्तांतरण बिना कलेक्टर की अनुमति के न केवल अवैध है, बल्कि दंडनीय भी है। नरेंद्र यादव ने ज्ञापन में प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा, पण्डो जनजाति सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि अपनी पहचान और वजूद की लड़ाई लड़ रही है। यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो पण्डो समुदाय के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। ज्ञात हो कि पण्डो जनजाति को राष्ट्रपति द्वारा दत्तक पुत्र की उपाधि दी गई है, बावजूद इसके, आज भी उन्हें अपनी जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से बताया गया कि यह जमीन वर्षों से झुरई पण्डो के परिवार के नाम पर दर्ज थी, जिसे अब धोखे से अन्य के नाम कर दिया गया। इस प्रकरण में स्थानीय राजस्व अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पटवारी स्तर पर की गई गड़बड़ी से न केवल कानून का उल्लंघन हुआ है, बल्कि आदिवासी हितों की सीधी अनदेखी की गई है। कानूनी जानकारों के अनुसार, भू-राजस्व संहिता की धारा 165 और 170(ख) आदिवासी भूमि सुरक्षा की संवैधानिक व्यवस्था हैं। यदि यह साबित हो जाए कि बिना वैध प्रक्रिया या छल-कपट से नामांतरण किया गया है, तो भूमि को शून्य घोषित कर उसे मूल आदिवासी परिवार को लौटाया जा सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता शुभम अग्रवाल ने भी मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा, पण्डो जैसे विशेष पिछड़े समुदाय के साथ हो रहा यह व्यवहार शर्मनाक है। सरकार और प्रशासन को न केवल जमीन लौटानी चाहिए, बल्कि दोषियों को दंडित कर एक सख्त संदेश देना चाहिए।

मंगनार में जैविक दवाओं का निर्माण, किसानों को मिलेगी नई दिशा

दंतेवाड़ा/मूक पत्रिका

जिले के मंगनार ग्राम की अम्मा स्व-सहायता समूह की 10 महिलाएं अब सामूहिक रूप से जैविक कृषि दवाओं का उत्पादन कर रही हैं। यह पहल एचडीएफसी बैंक परिवर्तन एवं वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास से शुरू हुई है। वर्तमान में महिलाएं ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, ईएम-2 घोल तथा निर्मास्त्र जैसे उत्पाद तैयार कर रही हैं। ये दवाएं पौधों की वृद्धि, पोषक तत्वों के अवशोषण और कीट-पतंग नियंत्रण में अत्यंत प्रभावी हैं। चूंकि दंतेवाड़ा जिला जैविक जिला घोषित है, यहां रासायनिक दवाएं उपलब्ध नहीं होतीं। ऐसे में यह जैविक उत्पादन किसानों के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो रहा है। इच्छुक किसान इन दवाओं को मंगनार स्थित बायो रिसोर्स सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। किसानों में इन उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। इन जैविक दवाओं के उपयोग से फसल उत्पादन में सुधार, लागत में कमी और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो रही है। साथ ही, रासायनिक दवाओं पर निर्भरता घट रही है और सतत कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। महिलाएं इसे अपने आजीविका सशक्तिकरण का माध्यम मानते हुए पूरे समर्पण से कार्य कर रही हैं। यह पहल जिले में जैविक खेती को नई दिशा दे रही है और अन्य समूहों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है।

दंतेवाड़ा में आयुष स्वास्थ्य चिकित्सा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन

स्थानीय हॉट बाजार में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ लिया

दंतेवाड़ा/मूक पत्रिका

जिला कलेक्टर कुणाल दुधावत के निर्देशानुसार, जिला आयुष अधिकारी बसंत कोसरे दंतेवाड़ा के द्वारा विकासखण्ड अंतर्गत निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य चिकित्सा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसी तारम्य में नोडल प्रभारी डॉ जितेंद्र कुमार शर्मा की अगवाई में 6 अगस्त 2025 (बुधवार) को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक दंतेवाड़ा विकासखण्ड के कातीयाररास (हाट बाजार) मे आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। जिला आयुष अधिकारी द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश में संबंधित विकासखण्ड के समस्त आयुष चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे। शिविर में स्थानीय ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने के लिए निःशुल्क आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी आदि पद्धतियों से स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार व सलाह दी गई। नोडल प्रभारी जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाना तथा आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। नोडल प्रभारी शर्मा ने स्थानीय नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है। *शिविर का शुभारंभ करने पहुंचे दंतेवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पायल गुप्ता ,उपाध्यक्ष गुप्त कैलाश मिश्रा, पार्षद श्रवण कडती ने उद्घाटन पश्चात अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। श्रीमती पायल गुप्ता ने बताया यूनानी पद्धति ,होम्योपैथी, आयुर्वेद पद्धति को सराहते हुए आम जनता से अपील करते हुए कहा आयुर्वेदचिकित्सा पद्धति आदिकाल से चली आ रही है। इस पद्धति का इस्तेमाल कर बिना साइड इफेक्ट के लंबे समय तक स्वस्थ रहा जा सकता है। उपाध्यक्ष गुप्त कैलाश मिश्रा ने कहा कि आज के जीवन की दिनचर्या मैं आयुर्वेद पद्धति का इस्तेमाल करके पूर्ण रूप से स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सकता है। स्वास्थ्य शिविर में 532 मरीज ने स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर यूनानी, होम्योपैथी एवं आयुर्वेद दवाइयां का निशुल्क लाभ लिया। मेगा स्वास्थ्य शिविर में डॉ.भागीरथी भूआत्र्य , डॉ. किशन लाल ठाकुर, डॉ.प्रमिला कोसेरे, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी डॉ.डॉली ठाकुर, यूनानी चिकित्सा अधिकारी डॉ मधु साहू, फार्मासिस्ट नेतराम कंवर, जगदेव साहू,जागेश्वर कंवर, श्रीमती हुलेश्वरी पैकरा, श्रीमती रजनी कश्यप, रूपेश कुमार नायक, जुगधर बारसा, दुलसाय सोढ़ी उपस्थितथे।

विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने कांवरियों पर किया पुष्पवर्षा से स्वागत, क्षेत्र में बनी ऐतिहासिक चर्चा

- प्रतापपुर के शिवपुर में हजारों श्रद्धालुओं की टोली ने शिवपुर धाम में जताई भक्ति , भव्य भंडारे का हुआ आयोजन

प्रतापपुर/मूक पत्रिका

सावन की भक्ति और श्रद्धा के महासंगम में इस वर्ष प्रतापपुर क्षेत्र ने एक नया इतिहास रचा, जब स्थानीय विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने शिवपुर धाम पहुँचकर हजारों कांवरिया बमों पर पुष्पवर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। इस भावनात्मक दृश्य ने जनमानस में गहरी छाप छोड़ी, और क्षेत्र में चर्चा का प्रमुख विषय बना। तथा क्षेत्र के खुशहाली के लिए शिव मंदिर में पूजा रुद्राभिषेक की क्षेत्र की खुशहाली के लिए कामना की। विधायक के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी इस श्रद्धा के संगम में सहभागी बने। पुष्पवर्षा के इस अद्वितीय क्षण में विधायक ने कांवरियों को शिवभक्ति और संयम की मिसाल बताते हुए उनका उत्साहवर्धन किया।

शिवपुर धाम में भव्य भंडारा, पोड़ी मोड़ पर स्वल्पाहार

शिवपुर धाम परिसर में भव्य भंडारे का आयोजन विशेष रूप से विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के सौजन्य से संपन्न हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पोड़ी मोड़ पर आयोजित स्वल्पाहार चन्द्रिका कुशवाहा, विजय यादव एवं अन्य गणमान्य नागरिकों की प्रमुख उपस्थिति रही, जिन्होंने आयोजन को भक्ति और सेवा का उत्सव बताया।

कांवर यात्रा का नेतृत्व शिक्षक बम करमचंद गुप्ता ने किया

ग्राम हरिहरपुर, परमेश्वरपुर, मटिगढ़ा, गोंदा, मरहठा, दुरती, भैसामुंडा, केवरा, दरहोरा, पोड़ी मोड़, सरहरी, प्रतापपुर सहित अनेक गांवों की कांवरिया टोलियों का नेतृत्व शिक्षक बम करमचंद गुप्ता एवं उनके सहयोगी साथियों द्वारा किया गया।

डीजे साउंड के साथ नाचते-गाते कांवरिया बम ÷हर हर महादेव÷, ÷बोल बम÷ के जयकारों से गूंजते हुए शिवपुर धाम पहुंचे, जहाँ उन्होंने बाबा जलेश्वरनाथ का जलाभिषेक कर पुण्य अर्जित किया।

शिवभक्ति और सामाजिक समरसता का संगम

इस विशाल आयोजन में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकता और सेवा भावना की मिसाल देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने इस आयोजन को ÷सावन की सबसे ऐतिहासिक कांवर यात्रा÷ बताते हुए इसे स्थानीय नेतृत्व और जनसमर्थन का एक प्रेरणादायक स्वरूप माना।

मुख्य आकर्षण बिंदु

विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते द्वारा पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत, मंडल अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल व जनप्रतिनिधियों की सहभागिता, शिवपुर धाम में विधायक द्वारा आयोजित विशाल भंडारा, पोड़ी मोड़ पर चन्द्रिका कुशवाहा व विजय यादव की उपस्थिति में स्वल्पाहार, शिक्षक बम करमचंद गुप्ता के नेतृत्व में हजारों श्रद्धालुओं की अनुशासित कांवर यात्रा, क्षेत्र में भक्ति, समर्पण और उत्सव का माहौल।

विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ने वाले विद्यामितान' खुद असुरक्षित, 8 साल से व्याख्याता समान कार्य, फिर भी न नियमितीकरण, न सम्मान

सूरजपुर/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बने अतिथि शिक्षक (विद्यामितान) वर्षों से शोषण और उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। व्याख्याता के पद पर बैठकर नौकरी की नहीं, जिम्मेदारी की भावना से कार्य कर रहे इन शिक्षकों को न सरकार ने नियमित किया, न भविष्य का भरोसा दिया। इसी अन्याय के खिलाफ आज विद्यामितान संघ के जिला प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से उनके गृहग्राम बीरपुर (सूरजपुर) में मुलाकात कर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंत्री महोदया ने शिक्षकों की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि आप सभी का कार्य सराहनीय है। आपकी मांगों को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगी और जो भी नियमानुसार संभव होगा, वह अवश्य किया जाएगा।

लेकिन शिक्षकों में अब भी आश्वासनों को लेकर संदेह है, क्योंकि यह पहली बार नहीं, जब उन्हें वादा' मिला है... सवाल है, कब मिलेगा फैसला'?

8 वर्षों से झुलसते विद्यामितान, फिर भी लाचार क्यों?-2016 से व्याख्याता पद पर स्नातकोत्तर एवं बीएड योग्यताधारी अतिथि शिक्षक सेवा दे रहे हैं। बोर्ड परीक्षा से लेकर द्धुष्टञ्ज, हस्स्, छात्रवृत्ति, निर्वाचन तक – हर जिम्मेदारी निभाई, लेकिन सरकार ने नहीं निभाई अपनी। बच्चों का भविष्य संवारने वाले शिक्षक आज खुद अपने भविष्य को लेकर भयभीत हैं। शिक्षकों ने बताया कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने ही सरगुजा व बस्तर में विद्यामितान योजना शुरू की थी, जिसे बाद में प्रदेशभर में लागू किया गया। अब वही सरकार सत्ता में है, फिर भी शिक्षकों के जीवन में स्थायीत्व नहीं।

ज्ञापन में रखी गई ये 5 निर्णायक मांगें- 12 माह का नियमित मानदेय तत्काल प्रभाव से प्रदान किया जाए। नियमित शिक्षकों जैसी शासकीय अवकाश की पात्रता सुनिश्चित की जाए। अतिथि शिक्षक के नाम को बदलकर 'व्याख्याता विषय' घोषित किया जाए। समान कार्य, समान वेतन (बेसिक ?38,100) दिया जाए। सेवा अवधि कम से कम 62 वर्ष तक सुनिश्चित की जाए।

शासन का पुराना आदेश खुद सवालों के घेरे में-पूर्व में जारी कई आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि जहां विद्यामितान कार्यरत हैं, वहां सीधी भर्ती, पदोन्नति या स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। तो क्या ये मान लिया गया है कि वे पद भर चुके हैं? अगर हाँ, तो फिर सरकारी दर्जा और वेतन से वंचित क्यों? और अगर नहीं, तो फिर किसे गुमराह कर रही है सरकार?

प्रतिनिधिमंडल में रहे ये शिक्षक-राज यादव, त्रिभुवन साहू, दीपेंद्र राजवाड़े, हसनैन खान, विकास गुप्ता, प्रेम साहू, शुक्ला जी एवं अन्य शिक्षकों ने मंत्री के समक्ष अपनी मांगों को ठोस तथ्यों के साथ रखा।अब सवाल जनता का है कि क्या विद्यामितान का भविष्य तय करेगी सरकार? या फिर रहेंगे ये शिक्षक वादा-पत्रों के भरोसे?

पुनरीक्षित हॉफबिजली बिल योजना से दुर्ग रीजन के 03 जिलों के 03 लाख 22 हजार सामान्य और कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को मिलेगा पूर्ववत लाभ

01 लाख 27 हजार बीपीएल परिवारों को मिलती रहेगी मुफ्त बिजली की सुविधा

बेमेतरा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने वाली हॉफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 400 यूनिट की मासिक छूट की सीमा में युक्तियुक्त संशोधन करते हुए अब 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया है। पुनरीक्षित हॉफ बिजली बिल योजना के तहत दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत दुर्ग जिले में लगभग 01 लाख 39 हजार 80 उपभोक्ता, बालोद जिले में लगभग 81 हजार 755 एवं बेमेतरा जिले में लगभग 01 लाख 01 हजार 287 जरूरतमंद सामान्य एवं कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ पूर्ववत मिलता रहेगा। इनमें दुर्ग क्षेत्र (दुर्ग,बालोद,बेमेतरा जिले) के लगभग 01 लाख 27 हजार बीपीएल(गरीबी रेखा से नीचे) परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें पूर्ववत 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। इसके साथ ही वे हॉफ बिजली बिल योजना के तहत अन्य सभी लाभों से भी यथावत लाभान्वित रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी तेज़ी से लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को रूफ्टॉप सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र और राज्य सरकारों से अधिकतम ?1,08,000 रूपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत 02 किलोवॉट प्लांट से प्रतिमाह औसतन 240 यूनिट उत्पादन संभव है, जिस पर ? 90,000 तक कुल सब्सिडी (? 60,000 केंद्र . ? 30,000 राज्य) मिलती है। 03 किलोवॉट क्षमता के प्लांट से प्रतिमाह औसतन 360 यूनिट उत्पादन संभव है, और इसमें ? 78,000 केंद्र . ? 30,000 राज्य यानी कुल ?1,08,000 की सहायता मिलती है। शेष राशि के लिये जो उपभोक्ता बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, उनके लिये आकर्षक एवं न्यूनतम वार्षिक ब्याज दर 6.3 से 6.5 प्रतिशत् एवं कम से कम दस्तावेज यथा बिजली बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेंडर कोटेशन एवं फीजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण भी उपलब्ध है। ज्ञात हो कि दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले के 911 परिवार सोलर पैनल लगाकर ना केवल मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं, बल्कि बिजली के भारी-भरकम बिलों से भी राहत पा रहे हैं। वर्तमान में मार्केट में विभिन्न कंपनियों के डी.सी.आर. सोलर पैनल उपलब्ध है। जिनके 03 किलोवॉट तक के सिस्टम की कीमत 1.8 से 2.10 लाख तक है। इस प्रकार उपभोकता के 03 किलोवॉट के सोलर प्लांट पर रू. 1,08,000 की सब्सिडी घटाकर शेष राशि स्वयं वहन करना होता है। बाजार में सोलर प्लांट का बीमा भी कई बीमा कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 2 किलोवॉट या अधिक क्षमता वाले प्लांट लगाने वाले उपभोक्ता प्रतिमाह 240 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन 25 साल तक कर सकते हैं, जो 03 अगस्त 2025 के पहले लागू हॉफ बिजली योजना से मिलने वाली अधिकतम छूट (400 यूनिट पर 200 यूनिट रियायत) से भी ज्यादा है। ऐसे उपभोक्ता अपने घर में सौर ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत का उपयोग कर न सिर्फ बिजली खर्च से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में प्रवाहित कर आय भी अर्जित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली, स्थायी बचत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करेगी। साथ ही, पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व निभाने की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम साबित होगा। इससे छत्तीसगढ़ के उपभोक्ता हॉफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली बिल योजना की ओर स्वाभाविक रूप से अग्रसर होंगे। उपभोक्ता किसी भी योजना पर निर्भर न रहते हुए स्वयं अपनी छत पर ऊर्जा उत्पादन कर उर्जादाता बनेंगे। यह रणनीतिक पहल राज्य को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक बचत और ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाएगी। इस योजना का लाभ उपभोक्ताओं को पूर्णतः आनलाइन प्रकिया के तहत दिया जा रहा है। जिसके तहत उपभोक्ता स्वयं ऑनलाईन पोर्टल https://pmsuryaghar.gov.in/#/ पर लॉग इन कर अथवा पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप, सीएसपीडीसीएल के वेबसाइट, मोर बिजली ऐप एवं बिजली कंपनी की टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए सीएसपीडीसीएल के नजदीकी बिजली दफ्तर में संपर्क कर सकते है। इस स्कीम के तहत उपभोक्ता सौर प्लांट के स्थापना हेतु वेंडर का चयन ऑनलाइन खुद कर सकते हैं। सौर प्लांट स्थापित होने के बाद केन्द्र एवं राज्य से प्राप्त होने वाली सब्सिडी राषि सीधे उपभोक्ता के खाते में अथवा बैंक से लोन लेने वाले प्रकरण में सीधे बैंक के खाते में प्राप्त होगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और एक उज्ज्वल और हरित भविश्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।

जनभागीदारी से करें आदिवासी बाहुल्य ग्रामों का समग्र विकास: मुख्यमंत्री ने आदि कर्मयोगी अभियान की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

रायपुर/मूक पत्रिका

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीते बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देशित किया कि आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से आदिवासी बाहुल्य ग्रामों का समग्र विकास जनभागीदारी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान के तहत पूरे देश में आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में 20 लाख स्वयंसेवकों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य की भागीदारी सक्रिय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1,32,400 वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे जनभागीदारी और जनजागरूकता के माध्यम से समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना है। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि युवाओं को वॉलंटियर्स के रूप में रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने की कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य गांवों में बुनियादी अधोसंरचना और सुविधाओं में जो भी 'क्रिटिकल गैप' शेष हैं, उनकी पहचान की जाए और आगामी 2 अक्टूबर 2025 को ग्राम सभाओं में इस पर विशेष चर्चा की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इन कमियों को दूर करने के लिए स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आवश्यक ठोस कदम उठाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि हर ग्राम बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त हो।

बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत ग्रामों में 'आदि सेवा केंद्र' स्थापित किए जाएंगे, जो न केवल मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में सहायक होंगे, बल्कि योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सतत क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बताया कि जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में धरती आबा और पीएम-जनमन जैसे संतृप्तिमूलक अभियानों की भी शुरुआत की गई है, जिनके अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्रामों एवं पीवीटीजी बस्तियों में आवास, पक्की सड़कें, जलापूर्ति, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 से 28 जुलाई 2025 के मध्य सम्पन्न किया जा चुका है तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स की सूची भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। आगामी गतिविधियों में जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण सहित अन्य कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिन्हें शीघ्र क्रियान्वित किया जाएगा।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, संयुक्त सचिव डॉ. रवि मित्तल, आदिम जाति कल्याण विभाग के आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

न्यायालय के कड़े निर्देश और बार-बार फटकार के बावजूद आंख मूंदे बैठी है गौ हत्यारी सरकार

बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गौठान बंद करने का दुष्परिणाम सड़को पर दिख रहा है, गौ अभ्यारण्य और गौ धाम का दावा कागजी

रायपुर/मूक पत्रिका

सड़कों पर मनवेशियों की मौत और रोज-रोज हो रहे हादसों को लेकर हाई कोर्ट के सख्त निर्देश को राज्य सरकार की अकर्मण्यता करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गौठान योजना बंद करने का दुष्परिणाम सड़कों पर दिख रहा है, गौ अभ्यारण्य और गौ धाम का दावा केवल कागजी है असलियत यह है कि भाजपा सरकार की उपेक्षा, पूर्वाग्रह और दुर्भावना के चलते ही गायें सड़कों पर कुचली जा रही हैं, किसान खुली चराई से परेशान हैं और राहगीर भी दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। विगत दिनों मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की संयुक्त पीठ में सुनवाई के दौरान सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं, सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सड़कों पर मवेशियों को हटाने टीम बनाए, रात में गस्त करें, हाईवे अथॉरिटी क्या कर रही है? गायों के गले पर रेडियम बेल्ट पहनाए जाए, आपका काऊ कैचर खाली पड़ा हुआ है, केवल दिखाने के लिए खड़ा किए जाते हैं? विगत 6 माह के भीतर जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक 6 दर्जन से अधिक गौवंशी पशुओं के साथ ही 55 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है लेकिन सरकार का रवैया शुतुरमुर्ग की तरह है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा गाय, गोबर और गौ मूत्र के नाम पर केवल राजनीति करती है, असलियत यह है कि विगत डेढ़ साल में छत्तीसगढ़ में गौवंशी पशुओं की संख्या तेजी से घट रही है, गौ तस्करी बढ़ी है, सड़क दुर्घटनाओं के तादाद में बेतहाशा वृद्धि हुई है। विगत दिनों बारीडीह के पास 17 गायें कुचल कर मारी गई, बिलासपुर मे 25 गाय कुचली गयी, इससे पहले रतनपुर बिलासपुर मार्ग पर 12 गायें, दामाखेड़ा के पास 9 गायें मारी गई, किरना में 18 गाये बेरहमी से रौंद कर मार दी गई विगत दो महीने के भीतर एक साथ बड़ी संख्या में हाईवे पर गायों के कुचल कर मारे जाने की ये चौथी बड़ी घटना है। नगरीय निकायों, पंचायत और हाईवे अथॉरिटी में आपस में समन्वय नहीं है जमीनी स्तर पर यह सरकार कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं कर पाई, इसी की वजह से हादसे थमने का नाम नहीं ले रहा है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि केवल पशुपालकों पर एफआईआर करना समस्या समुचित उपाय नहीं है, गैर बीमित पशुओं के मालिकों को चिन्हित करना आसान नहीं है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान गोबर और गौ मूत्र खरीदी की वजह से गौ वंशी पशु बांध कर रखे जाते थे अब दूसरे गांव और सड़कों पर खुले घूम रहे हैं। कांजी हाउस खाली पड़े हैं। भाजपा की सरकार की गौ संरक्षण को लेकर ना कोई नीति है ना ही नियत। नई व्यवस्था तो छोड़िए पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थापित 10 हजार से अधिक गौठान जिसमें से लगभग 8 हजार गौठान आत्मनिर्भर हो चुके थे, गौठान समिति और महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा संचालित होने वाली उस सुव्यवस्थित योजना के संचालन में भी यह सरकार नाकाम रही।

केन्द्रीय रेल मंत्री से सांसद संतोष पाण्डेय की सौजन्य मुलाकात

मूक पत्रिका/ राजनांदगांव - केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पाण्डेय ने दिल्ली में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर सांसद पाण्डेय ने राजपुर-जबलपुर रेल सेवा प्रारंभ करने हेतु मंत्री वैष्णव का आभार व्यक्त किया।

सांसद पाण्डेय ने कहा कि यह बहुप्रतीक्षित रेल सेवा प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ के महाकौशल क्षेत्र से सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा, जिससे आवागमन के साथ-साथ व्यापारिक एवं सामाजिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। उन्होंने इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

सोने,चांदी के जेवर एवं नगदी रकम चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता

मूक पत्रिका/बेमेतरा - जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू के निर्देशन में अपराध एवं अवैध गतिविधियों पर लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस टीम ने एक चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है।

बेमेतरा, 04 अगस्त 2025 को प्रार्थिया कलिन्द्री साहू पति स्व. गौकरण साहू उम्र 60 वर्ष, निवासी मेहना थाना नांदघाट जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 03,04/08/25 के दरिमियानी रात में कोई अज्ञात चोर मेरे घर का दरवाजा का कब्जा को तोडकर घर अंदर घुसकर पेटी के अंदर रखे 02 लाख 15 हजार रूपये नगदी, पेटी के अदंर एक बैग था जिसमें चांदी का 2 कडा (एठी), 8 नग चुडी (पटा), चांदी का 2 नग चैन, 2 जोडी चांदी का पायल, 1 चांदी का चाबी रिंग, 1 नग चांदी का बच्चे का करधन, 2 जोडी कान की खुंटी, 1. नग सोने का फुल्ली, 2 नग सोने का लाकेट एवं अन्य चांदी के चुडी, किमती करीबन 50,000/-रू. था जुमला कीमती करीबन 02 लाख 65 हजार रुपये को चोरी कर ले गया कि रिपोर्ट पर थाना नांदघाट में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 331(4), 305() ब्हृस्- के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

*घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार, अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह एवं एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नांदघाट उप निरीक्षक भुनेश्वर यादव व थाना स्टाफ को अज्ञात आरोपी की पता तलास हेतु त्वरित टीम गठित कर माल, मुल्जिम पता साजी में लगाया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते जरिये मुखबीर सूचना पर आरोपी राकेश साहू ऊर्फ लल्लू उम्र 32 वर्ष, निवासी मेहना थाना नांदघाट को घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पुछताछ की गई। पुछताछ करने पर अपना जुर्म करना स्वीकार किया।

आरोपी के कब्जे से नगदी रकम 19,500/- रूपये, मोबाईल स्क्रीन टच कीमती 33,000/- रूपये, यामहा बाईक मोसायकल कीमती 1,50,000/- रूपये एवं दो नग सोने का लाकेट, दो जोडी चांदी का पायल, एक नग चांदी का चाबी रिंग, एक नग चांदी का चैन, तीन नग चांदी का अंगुठी, 15 नग चांदी का बिछिया, दो नग चांदी की चुडी, 05 नग सोने की फुल्ली, एक नग चांदी का टुटा पायल कुल कीमती 41,400/- रूपये, कुल जुमला कीमती 2,43,900/- रूपये (2 लाख 43 हजार 9 सौ) को जप्त कर बरामद किया गया।

आरोपी राकेश साहू ऊर्फ लल्लू पिता डेरहा साहू उम्र 32 वर्ष, निवासी मेहना थाना नांदघाट जिला बेमेतरा को बीते 05 अगस्त 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया।

भाजपा का तिरंगा अभियान केवल दिखावे के लिये

- आम आदमी तो अपने घरों में तिरंगा फहराता है, संघ की शाखाओं में क्यों तिरंगे से परहेज?
- भाजपा का तिरंगा यात्रा केवल राजनीतिक पाखंड, ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने को लेकर ट्रंप के दावे पर भाजपाई खामोश

रायपुर/मूक पत्रिका

भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा अभियान को राजनीति के पाखंड करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि तिरंगा हर भारतीय के लिए आन बान शान है, लेकिन भाजपाइयों के लिए यह केवल राजनैतिक विषयवस्तु है। भाजपा का राष्ट्रवाद और तिरंगा प्रेम केवल दिखावा है, असलियत में तिरंगा के प्रति भाजपाइयों के मन में हिकारत है भाजपा तो मुखौटा है उनके पित्र संगठन के लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का बार-बार अपमान किया तीन रंग को अपशगुन बताएं, अब केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए घर घर यात्रा निकाल रहे हैं। भाजपा के तय कार्यक्रम के अनुसार तिरंगा यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर को जोड़े जाने को मोदी सरकार की नाकामी पर परदेदारी करार देते हुए कहा कि सेना के शौर्य पर राजनीति करना भाजपा का चरित्र बन चुका है। पुलवामा और गलवान पर भाजपाई मौन हो जाते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 32 बार यह दावा किया है कि उन्होंने व्यापार का लालच देकर अपने सिंदूर स्थगित करवाया, मोदी, शाह सहित तमाम भाजपाई इस पर मौन क्यों है? पहलगाम हमले के साढ़े तीन महीने बाद भी आज तक आतंकी ना पकड़े गए ना ही उन्हें मारे गया किसके संरक्षण में वे भागे, सुरक्षा में गंभीर चूक के लिए जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही की गई? भाजपा बताये आजादी के बाद 52 सालों तक संघ के मुख्यालय नागपुर में तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया था? आजादी के बाद दशको तक भाजपा के पितृ संगठन आरएसएस ने क्यों राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार नहीं किया था?

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा भाजपाई आत्म अवलोकन करें कि उनके पूर्वजों ने क्यों तिरंगे को अपमानित किया था। आज भी संघ के शाखाओं में तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता? देशवासी तो गर्व से अपने घरों में तिरंगा फहराते है, संघ की शाखाओं में तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस ने ही 1929 में लाहौर अधिवेशन के समय रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, उसके बाद से हर साल 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाने लगा। आजादी की 77वीं वर्षगांठ पर देश भक्ति का जलसा निकालने की नौटंकी करने वालों के पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों के पैरोकार की भूमिका में खड़े थे। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश की आन-बान-शान का प्रतीक रहे तिरंगा को भाजपा ने पितृ पुरुष गोलवलकर ने देश के लिये अपशगुन बताया था। तिरंगे के प्रति सम्मान का आडंबर कर रही भाजपा के आदर्श गोलवलकर ने अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज मानने से ही मना कर दिया था। इस पुस्तक में उन्होंने लोकतंत्र और समाजवाद को गलत बताते हुए संविधान को एक जहरीला बीज बताया था। 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर में लिखा था ÷तीन शब्द ही अशुभ है, तीन रंगों वाला झंडा निश्चित तौर पर बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करेगा और देश के लिये हानिकारक साबित होगा।÷ 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गयी तो अखबारों के माध्यम से खबरें आई थीं कि आरएसएस के लोग तिरंगे झंडे को पैरों से रौंदकर खुशी मना रहे थे। आज़ादी के संग्राम में शामिल लोगों को आरएसएस की इस हरकत से बहुत तकलीफ हुई थी।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के पितृ संगठन आरएसएस के मूलस्वरूप हिन्दू महासभा का गठन 1925 में हुआ, देश आजाद 1947 में हुआ इन 22 सालों तक भारत के आजादी की लड़ाई में हिन्दू महासभा का क्या योगदान था? भाजपाई बता नहीं सकते। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब दीनदयाल उपाध्याय 32 वर्ष के परिपक्व नौजवान थे, देश की आजादी की लड़ाई में उनका क्या योगदान था? कितनी बार जेल गये? 1942 में कांग्रेस महात्मा गांधी की अगुवाई में भारत छोड़ो आंदोलन चला रही थी, तब भाजपा के पितृ पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजी हूकूमत को सलाह दे रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन को क्रूरतापूर्वक दमन किया जाना चाहिये। अंग्रेजो के इशारे पर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में अंतरिम सरकार बनाये। ऐसी विचार धारा वाली भाजपा की तिरंगा यात्रा निकालना केवल राजनैतिक ढोंग है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एनीमिया मुक्त रथ को हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ

मूक पत्रिका/दंतेवाड़ा - प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टरेट परिसर से ÷एनीमिया मुक्त रथ÷ को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। यह रथ जिले में एनीमिया की रोकथाम एवं जन जागरूकता के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जाकर लोगों को एनीमिया के लक्षण, कारण, बचाव एवं उपचार की जानकारी देगा।

इस अवसर पर अध्यक्ष सीजीएमएससी दीपक महस्के, विधायक चैतराम अटामी, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, अन्य जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं श्रीमती प्रियंका शुक्ला, कलेक्टर कुणाल दुदावत, जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा तथा स्वास्थ्य एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम)योजना'' हेतु तीर्थयात्रियों को किया गया रवाना

मूक पत्रिका/दंतेवाड़ा - समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना ''श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना'' के तहत दिनांक 06 अगस्त 2025 से 09 अगस्त 2025 तक की तीर्थयात्रा हेतु दंतेवाड़ा जिले से बीते 05 अगस्त 2025 को 28 तीर्थयात्रियों की बस को विधायक चैतराम अटामी, अध्यक्ष जिला पंचायत नंदलाल मुड़ामी एवं अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमती पायल गुप्ता द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

गीदम पुलिस द्वारा महाराष्ट्र ,राजस्थान के बाद केरल राज्य से तीन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

वर्क फार्म होम के नाम पर फर्जी कम्पनी (द गुड गाईस इलेक्ट्रानिक कंपनी) द्वारा लगभग 61 लाख की ठगी करने वाले पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही

मूक पत्रिका/दंतेवाड़ा - पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा गौरव राय द्वारा सायबर ठगी के मामलो को गम्भीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के. बर्मन के मार्ग दर्शन एवं एसडीओपी बारसूर गोविन्द दीवान के पर्यवेक्षण मे सायबर सेल प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक गौरव ठाकुर के नेतृत्व में हमराह निरीक्षक विजय पटेल गीदम पुलिस द्वारा सायबर ठगी पर कार्यवाही करते हुए आरोपी के संबंध में जानकारी एवं पता तलाश हेतु आवश्यक कार्यवाही वास्ते टीम का गठन कर अथक प्रयास के बाद केरल राज्य से तीन आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया है। सायबर ठगी के संबंध में आवेदक भूपेन्द्र तेलामी ग्राम हारम थाना गीदम जिला दंतेवाड़ा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि वॉटसअप पर वर्क फार्म होम के नाम पर कम्पनी (द गुड गाईस इलेक्ट्रानिक कंपनी) का प्रति दिन कार्य कर 1200- 6000 रूपये कमाने का मेसेज आया। जिससे वह जूड गया जूडने के बाद उसके वैलट में 10000/- रू0 आ गया फिर डेमो करने को कहा गया जिसमें 20 टेण्डर को ओपन करना होता है टेण्डर में इलेक्ट्रानिक समान होता है जिसमें से प्राफिट निकल कर लाभ में शामिल होता जाता है टेण्डर पूरा करने के बाद लगाया हुआ राशि और लाभ एक साथ आवेदक के बैंक

खाते में ट्रांसफर कर दिया लाभ देखकर आवेदक टेलिग्राम से जूड गया जिसमें आवेदक को फायनेन्सियल कन्सलटेंट से सम्पर्क करने को कहा गया जिसके बाद आवेदक को कई अलग-अलग खातों में पैसे डलवाकर लगभग 61 लाख रूपये की ठगी की गई मामले में थाना गीदम में अपराध क्रं. 27/2025 धारा- 318 बीएनएस, 66(डी) आई.टी.एक्ट का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था । विवेचना दौरान पूर्व में 10 नफर सायबर ठग आरोपियों को महाराष्ट्र, राजस्थान राज्य से गिरफ्तार किया गया था और उनके विरूद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के अन्य आरापियों की पता तलाश हेतु सायबर सेल प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक गौरव ठाकुर के हमराह निरीक्षक विजय पटेल गीदम पुलिस द्वारा त्वरित विधिसंगत कार्यवाही करते हुए केरल राज्य के अलग-अलग जगहों से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय दन्तेवाड़ा दिनांक 05.08.2025 प्रस्तुत कर जेल दाखिल किया गया।

नाम आरोपी 1.:- 01. लागिथ गणेश पिता गणेश उम्र 30 वर्ष साकिन कच्चीनरफम पीओ थाना चेवयुर जिला कोझीकोड राज्य केरल

02. जितिन पिता स्व. भास्कर उम्र 30 वर्ष निवासी वेल्लिमादुकुंन इरिन्गादंपल्ली कोवूर रोड पुलिस थाना चेवयुर जिला कोझिकोड राज्य केरल

03. मुनीर यूपी पिता कासिम उम्र 28 वर्ष निवासी पेरिंगलम कुन्नमंगलम पुलिस थाना कुन्नमंगलम जिला कोझिकोड राज्य केरल

ऽ आरोपीयों के पास से मोबाईल 02 नग, बैंक खाता पासबुक व नगदी रकम 1,600 रूपये जप्त किया गया ।

मामले में उप पुलिस अधीक्षक गौरव ठाकुर (सायबर सेल प्रभारी)निरीक्षक विजय पटेल सउनि प्रशांत सिंह , आरक्षक केशव पटेल, ईश्वर ठाकुर , मिथलेश पुजारी, विश्वनाथ नाग, की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

मूक पत्रिका की खबर से जागा प्रशासन – तिरिया पंचायत में भ्रष्टाचार की जांच शुरू, लेकिन क्या यह सिर्फ दिखावा है?

जगदलपुर (पवन कुमार नाग) – ग्राम पंचायत तिरिया में भ्रष्टाचार की परतें उधड़ीं÷ – मूक पत्रिका की यह खबर छपते ही बस्तर प्रशासन में हड़कंप मच गया। वर्षों से पड़ी फाइलें अब खुल रही हैं, और अफसरों की नींद टूट चुकी है। जो काम जनशिकायतों से नहीं हुआ, वो एक निर्भीक खबर ने कर दिखाया।

लेकिन क्या प्रशासन अब भी सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रहा है?

जांच या लीपापोती? : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जगदलपुर ने कहा कि ÷निष्पक्ष जांच होगी÷, लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है। बीते 5 अगस्त 2025, सुबह 11 बजे, पंचायत भवन तिरिया में उपस्थित रहने का फरमान तो जारी हुआ,

लेकिन वहीं दूसरी ओर, जांच अधिकारी टीएल बैठक का बहाना बनाकर सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं और लौट आ रहे हैं।

यह आचरण ग्रामीणों और खबर देखने वालों के लिए बड़ा सवाल बन गया है – क्या जांच टीम कुछ सचिवों को बचाने की कोशिश कर रही है?

क्या यह जांच भी बाकी मामलों की तरह सिर्फ कागज़ों में सिमट जाएगी?

पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों की गहराई से जांच हो : रखरखाव खर्च, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, और भुगतान प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हो और यदि किसी स्तर पर अनियमितता या गड़बड़ी मिलती है, तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन, यह सब सिर्फ कागजों पर न हो, यही जनता की मांग है।

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
मूक पत्रिका
निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...
जिला खनिज न्यास से बने शिक्षकों के लिए शासकीय भवन खंडहरों में तब्दील
भवन की बदहाल स्थिति: छह साल से वीरान पड़ा हुआ है भवन
बस्तर/जगदलपुर/मूक पत्रिका

मूक पत्रिका
प्रादेशिकी
तिरिया पंचायत में भ्रष्टाचार की परतें उधड़ीं – रखरखाव, नाली सफाई और सोलर लाइट में लाखों का घोटाला, सचिव का मीडियाकर्मी को धमकी भरा चैलेंज!
जगदलपुर/मूक पत्रिका

ग्रामीणों का गुस्सा और उम्मीद : ग्राम पंचायत तिरिया के ग्रामीणों ने वर्षों से भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता और अनदेखी का सामना किया है। कई बार शिकायतें हुई, लेकिन हमेशा की तरह उन्हें दबा दिया गया।

यह पहली बार है जब कोई अखबार ङ्क और वो भी ÷मूक पत्रिका÷ ङ्क ने जनता की आवाज़ बनकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है।

अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि यह मामला दबाया नहीं जाएगा।

लेकिन उनका भरोसा अब भी डगमगाया हुआ है, क्योंकि उन्हें पुराने अनुभवों की कीमत मालूम है।

मूक पत्रिका का ऐलान ङ्क कलम की लड़ाई अभी बाकी है : अगर इस बार भी जांच में गंभीरता और पारदर्शिता नहीं दिखाई गई,अगर दोषियों को बचाने की कोशिश हुई, तो ÷मूक पत्रिका÷ चुप नहीं बैठेगी।

हमने यह मुद्दा उठाया है ङ्क हम इसे अंजाम तक पहुँचाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मूक पत्रिका लगातार खबर चलाती रहेगी।÷यह लड़ाई सिर्फ तिरिया की नहीं, पूरे बस्तर की है!÷

अब बारी प्रशासन की है ङ्क या तो न्याय दे, या सवालों का सामना करे

मूक पत्रिका की कलम अब रुकने वाली नहीं है ङ्क जब तक हर भ्रष्टाचार को अंजाम तक नहीं पहुंचाती तब तक मूक पत्रिका की कलम चलती रहेगी ।

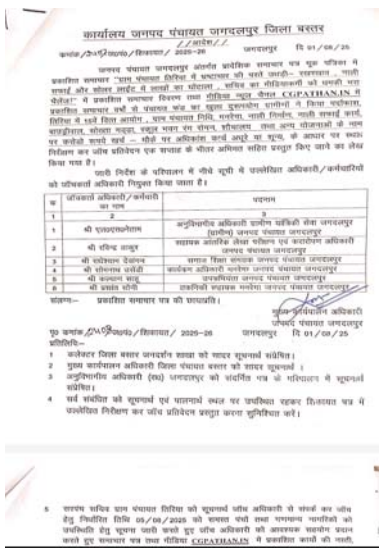

बस्तर के आश्रम-छात्रावास कर्मचारियों की एक सूत्रीय मांग : तुता, रायपुर में आमरण अनशन शुरू

मूक पत्रिका/ रायपुर —बस्तर जिला स्कूल, आश्रम एवं छात्रावासों में वर्षों से कार्यरत शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ, जगदलपुर के सदस्यों ने अपनी नियमितिकरण की एक सूत्रीय मांग को लेकर राजधानी रायपुर स्थित तुता धरना स्थल पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है।

संघ का कहना है कि ये कर्मचारी बीते कई वर्षों से आश्रम-छात्रावासों में भोजन व्यवस्था, साफ-सफाई, देखरेख, सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं का कार्य लगातार कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया है। इससे वेतन, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और अन्य मूलभूत अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है।

धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि वे कई बार ज्ञापन, प्रदर्शन, रैली और आवेदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार

की ठोस कार्यवाही नहीं हुई। अब वे अंतिम विकल्प के रूप में आमरण अनशन का रास्ता अपनाने को मजबूर हुए हैं।

संघ ने राज्य सरकार, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि आश्रम-छात्रावासों में कार्यरत सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तत्काल नियमित किया जाए, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।

इस आमरण अनशन को विभिन्न जनसंगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। वहीं धरना स्थल पर कर्मचारियों की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए चिकित्सकीय दल की तैनाती भी की गई है।

यदि शासन-प्रशासन ने समय रहते संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो यह आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन की होगी।

स्व. कर्मा की जयंती पर बस्तर टाईगर अमर रहे के लगे नारे

शहीद महेंद्र कर्मा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का लिया संकल्प

मूक पत्रिका/दन्तेवाड़ा – बस्तर टाईगर शहीद महेन्द्र कर्मा की बीते मंगलवार को 76 वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर उनके गृहग्राम फरसपाल में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक देवती महेन्द्र कर्मा द्वारा स्व. महेन्द्र कर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्व. कर्मा के सुपुत्र वरिष्ठ नेता छविन्द्र कर्मा, सुपुत्री जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा, सुलोचना कर्मा ने भी उनकी शहादत को नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं गायत्री मंदिर स्थित शहीद महेन्द्र कर्मा प्रतिमा पर कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कर स्व. कर्मा के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर पूर्व विधायक देवती कर्मा ने कहा कि बस्तर में शांति-बहाली के लिए स्व. कर्मा ने अपना सर्वस्त न्यौछावर कर दिया। जल, जंगल, जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए वे सदैव लड़ते रहे। शहीद महेन्द्र कर्मा का जीवन हम

सभी को अपने अधिकारों की रक्षा में प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा देता है। छविन्द्र कर्मा ने कहा कि पिताजी का स्नेह, त्याग और मार्गदर्शन हमारे लिए जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। भले ही आज वह हमारे बीच नहीं है परंतु उनके दिए हुए संस्कार और आदर्श आज भी हमें सही राह दिखाते हैं। तुलिका कर्मा स्व. महेन्द्र कर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका आशीर्वाद हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है साथ ही उनके सिखाएं हुए मार्ग पर ही चलना उन्हें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बस्तर में शांति बहाली के लिए कार्य किया। जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा ने कहा कि शहीद महेन्द्र कर्मा ने जो सपना देखा था उन्हें पूरा करना अब हमारी जिम्मेदारी है। आपसी भाईचारे व खुशहाल बस्तर का सपना लेकर वह चले थे, जिसे अब हमें पूरा करना है। इस दौरान प्रवीण राणा, विमल सलाम, सुमित्रा सोरी, इंदिरा शर्मा, इंद्रा ठाकुर, रिंकी वेंजाम, एन नागराज, गणेश दुर्गा, रितेश जैन, रानू राव, संजय विश्वकर्मा, त्रिशांक ठाकुर, जीतू कश्यप समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे।

नन्हें बच्चों को कराया भोजन व वृद्धजनों को किया फल वितरण– स्व शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती पर तुलिका कर्मा ने सक्षम के बच्चों के बीच पहुंची। यहां पहुंच उन्होंने सक्षम के बच्चों को भोजन कराया साथ ही स्व.कर्मा के याद में टिफिन बॉक्स का वितरण किया। वहीं सुलोचना कर्मा ने हारम पारा स्थित वृद्धाआश्रम पहुंच फल वितरण किया साथ ही कासोली बालक आश्रम पहुंच बच्चों को भी फल वितरण किया।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने बोदली उप स्वास्थ्य केन्द्र का किया निरीक्षण

- टीबी मरीजों को पोषण आहार, गर्भवती महिलाओं को फलकिट एवं आयुष्मान कार्ड वितरित
- किशोरी बालिका की आंखों की गंभीर समस्या के उपचार हेतु स्वास्थ्य मंत्री ने सीएमएचओ को किया निर्देशित

मूक पत्रिका/दन्तेवाड़ा – प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज दंतेवाड़ा जिले के बोदली स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी, प्रसव कक्ष, टीबी मरीजों की देखरेख तथा स्वास्थ्य रजिस्टरों के संधारण की स्थिति की बारीकी से समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान मितानिन बहनों ने पारंपरिक तरीके से मंत्री जायसवाल का स्वागत करते हुए उन्हें राखी बांधी। इस आत्मीय क्षण पर मंत्री ने मितानिनों को साड़ी भेंट कर सम्मानित किया और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदाय

के संबंध में प्रोत्साहित करते हुए यह आश्वासन दिया कि उनके मानदेय का भुगतान हर माह की 15 तारीख तक दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। जायसवाल ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से एचआरपी श्रेणी की गर्भवती महिलाओं को समय पर उच्च स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर करने, अंडा वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा मलेरिया मुक्त अभियान के तहत घर-घर जाकर जांच और उपचार की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए।

कार्यक्रम के दौरान एक भावुक क्षण तब आया जब ग्राम की एक बालिका कविता पुनेम ने अपनी आंखों की गंभीर समस्या के इलाज के लिए मंत्री से सहायता की गुहार लगाई। मंत्री जायसवाल ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को बच्ची को रायपुर रेफर करने के निर्देश दिए और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

निरीक्षण के उपरांत मंत्री द्वारा विभिन्न हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ प्रदान किए गए। इस अवसर पर उन्होंने टीबी से पीड़ित मरीजों को पोषण आहार, गर्भवती महिलाओं को फलकिट, पात्र ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना एवं वय वंदन योजना के कार्ड वितरित किए। साथ ही निष्ठा से सेवा दे रहे निक्षय मित्रों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान भी किया। मंत्री जायसवाल ने सभी स्वास्थ्यकर्मियों और अधिकारियों से क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सतत प्रयास करने का आह्वान किया और यह भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

इस मौके पर सीजीएमएससी अध्यक्ष दीपक महस्के, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, उपाध्यक्ष अरविन्द कुंजाम, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, आयुक्त एवं संचालक स्वास्थ्य सेवाएं श्रीमती प्रियंका शुक्ला, जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर राजेश पात्रे सहित प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

22 अगस्त को सभी स्कूल एवं कार्यालय रहेंगे बंद

- छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी रहेंगे हड़ताल पर

मूक पत्रिका/कोंडागांव – छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी 22 अगस्त 2025 को एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे जिसकी तैयारी के लिए कोण्डागांव में फेडरेशन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें संगठन की कसावट और प्रचार प्रसार के लिए जिले के टीम गठित कर पांचों विकास खंड माकड़ी, फरसगांव, केशकाल, बड़े राजपुर, कोण्डागांव में दौरा करेगा।

÷मोदी की गारंटी लागू करो÷ आंदोलन के अंतर्गत 22 अगस्त 2025 को प्रस्तावित जिला स्तरीय कलम बंदङ्कक़ाम बंद आंदोलन में सामूहिक अवकाश रहेंगे

*विदित हो कि 16 जुलाई 2025 को पूरे प्रदेश के हजारों कर्मचारी-अधिकारियों ने ÷मोदी की गारंटी लागू करो÷ आंदोलन में एकजुटता के साथ भाग लेकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था यह प्रदर्शन राज्य सरकार से लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की माँग को लेकर किया गया था।

11 सूत्रीय मांगें हर कर्मचारी की आर्थिक-सामाजिक गरिमा से जुड़ी हैं, जिनमें शामिल हैं-

केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता (ध्र) लागू किया जाए।

ध्र एरियर्स की राशि कर्मचारियों के त्नक्क्न खाते में समायोजित की जाए।

सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए।

विभिन्न वर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए।

प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा लाभ दिया जाए।

सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाए।

अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10 प्रतिशत सीलिंग में शिथिलीकरण की जाए।

प्रदेश में कैशलेश सुविधा लागू की जाए।

अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस की जाए।

दैनिक,अनियमित,संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की ठोस नीति बने।

सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जावे।

आज के इस बैठक में मुख्य रूप से जिला संयोजक शिवराज सिंह ठाकुर,उप संयोजक निर्मल कुमार शार्दूल, सहसंयोजक लोकेश गायकवाड़ महामंत्री संजय सिंह ठाकुर, मिडिया प्रभारी रामदेव कौशिक, सचिव हीरा नेताम, रमेश सोनपिपरे, कमलेश साहू, निवास नायडू, चमनलाल वर्मा, बलराम निषाद,ललीत कोर्राम, मदनलाल राठौर, सतीश शोढ़ी,सुकमन नेताम, राजकुमार मण्डावी, चन्दुलाल देशमुख जहांगीर खान, श्रीमती अर्चना बैनर्जी (महिला प्रकोष्ठ जिला संयोजक) ,पूजा कुंवर डी एस पोटाई, तुलसी नेताम, अमरजीत निर्मलकर आदि उपस्थित रहे।

घटना के सूचना बाद प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता के मद्देनजर पतासाजी हेतु विशेष दल गठित किया गया

ब्लाइंड मर्डर एवं दुष्कर्म की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को मिली सफलता

टीम द्वारा आस–पास के कई सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया एवं सायबर सेल द्वारा तकनीकी विश्लेषण किया गया

पालनार में लगातार संदिग्धो से तथ्यात्मक एवं सूक्ष्मता से पूछताछ एवं पतासाजी किया गया

दुष्कर्म एवं हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया

मूक पत्रिका/दन्तेवाड़ा – जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में महिला संबंधी अपराधों में संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधीक्षक गौरव राय(भा.पु.से.)जिला दन्तेवाड़ा के दिशा-निर्देशन एवंअतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार बर्मन(रा.पु.से.) के मार्गदर्शन एवं सुश्री कल्पना वर्मा एसडीओपी कुआकोंडा के पर्यवेक्षण में कुआकोंडा पुलिस द्वारा दुष्कर्म व हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

घटना दिनाक 25:07. 2025 के प्रात. करीबन 08.00 बजे ग्राम पालनार निवासी मृतिका उम्र 45 वर्ष साप्ताहिक बाजार पालनार में बाजार करने गई थी। जो शाम करीबन 04:00

बजे तक साप्ताहिक बाजार में ही शराब पीये हुए हालत में ईमली पेड़ के पास बैठी थी। मृतिका रात्रि ने अपने घर नहीं गई थी। दिनांक 26.07.2025 के प्रातः करीबन 07:00 बजे गांव की ग्रामीण महिलाएं बाजार की साफसफाई कर रही थी। उसी दौरान मृतिका के शव बाजार के ईमली पेड़ के पास बिना कपडों के मृत अवस्था में पड़ी थी। परिजनों के सूचना पर मौके पर पुलिस के द्वारा सूचक कि रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर परिजनों, गवाहों का कथन लेकर शव का पीएम कराकर शार्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर घटना दिनांक 25.07.2025 के शाम करीबन 04:00 से दिनांक 26:07:2025 के प्रातः करीबन 07:00 बजे के मध्य किसी अज्ञात आरोपी के द्वारा मृतिका के साथ दुष्कर्म कर उसके गुप्तांग में चोंट पहुंचाने से उसकी मृत्यु होने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 15/2025 धारा 66, 103 (1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान अज्ञात आरोपी की पता साजी हेतु पुलिस अधीक्षक दन्तेवाड़ा गौरव राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर के वर्मन के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कुआकोडा सुश्री कल्पना वर्मा के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी कुआकोडा निरीक्षक मोहर साय लहरे के नेतृत्व में लगातार पता साजी की जा रही थी। पतातलाश दौरान संदेही आरोपी भीमा राम मरकाम उर्फ बोडडा पिता स्व. कामा मरकाम उम्र 30 वर्ष साकिन पालनार मोसलटोडा थाना कुआकोडा जिला दन्तेवाडा की गतिविधियां संदेस्यापद था तथा घटना के समय घटनास्थल के आप-पास उपस्थिति पता चलने पर अभिरक्षा में लेकर तथ्यात्मक एवं बारिकी से पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत् दिनांक 05.08.2025 के 13.40 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दन्तेवाड़ा के समक्ष पेश कर जिला जेल भेजा गया।

कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिकाः- निरीक्षक मोहर साय लहरे थाना प्रभारी कुआकोंडा' उनि . रमेश मरकाम, प्र.आर मनोज तिवारी, किशोर पटेल' आर.315 झिमटू मण्डावी, आर.3130 परदेशी मण्डावी , आर .3151 लाली नेताम, आर. 659 राजू ओयामी' इस कार्यवाही मे शामिल रहै।

कलेक्टर रणबीर शर्मा ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश, जिले में 158 केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण, 135 नवीन मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव तैयार

मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक सम्पन्न

बेमेतरा/मूक पत्रिका

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के पूर्व, जिले में मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन (युक्तियुक्तकरण) की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस क्रम में 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों का पुनः परीक्षण कर उन्हें विभाजित कर नवीन केन्द्रों की स्थापना, स्थान परिवर्तन व भवन परिवर्तन हेतु प्रस्ताव आयोग को भेजा जाना है। इस अवसर पर एएससपी रामकृष्ण साहू, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज, एडीएम अनिल वाजपेयी, राजनीतिक दलों के सदस्य गण, निर्वाचन शाखा के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे .इसी संदर्भ में बीते बुधवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टरेट के दृष्टि सभाकक्ष मे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के निर्देशों के अनुरूप जिले में प्रस्तावित कार्य योजना की विस्तृत जानकारी साझा की गई एवं दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में बताया गया कि जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 158 ऐसे मतदान केन्द्र चिन्हित किए गए हैं जहां मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है। इन केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण करते हुए 135 नवीन मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें 14 केन्द्रों के अनुमोदन तथा 3 केन्द्रों के भवन परिवर्तन के प्रस्ताव भी शामिल हैं। प्रस्तावित नवीन मतदान केन्द्रों का विधानसभा क्षेत्रवार अंतर्गत साजा विधानसभा क्षेत्र मे 36 केन्द्र, बेरला विधानसभा क्षेत्र मे 41 केन्द्र और नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र 58 केन्द्र शामिल है .वर्तमान में जिले में कुल 7,99,737 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 4,00,561 पुरुष, 3,99,372 महिला एवं 4 अन्य मतदाता शामिल हैं 7 बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 01 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि को आधार मानते हुए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम पृथक रूप से जारी किया जाएगा। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित बनाए रखने हेतु वे अधिकतम सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सभी सुझावों का स्वागत किया जाएगा और प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु नियुक्त बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी। नवीन मतदान केन्द्रों की सूची अनुमोदन उपरांत सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके आधार पर प्रत्येक केन्द्र में बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) की नियुक्ति कर जानकारी साझा करना आवश्यक होगा। निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने हेतु वर्ष भर चार अर्हता तिथियां 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर निर्धारित की गई हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7, और संशोधन, स्थानांतरण, डुप्लीकेट ईपिक कार्ड या दिव्यांगजन को चिह्नित करने हेतु फॉर्म 8 का उपयोग किया जा सकता है। ये फॉर्म वोटर हेल्पलाइन एप्प या 1शह्लद्गह्म्.द्गष्द्ब.द्द1.द्बठ्ठ वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कभी भी भरे जा सकते हैं। एपिक कार्ड निर्माण का कार्य एमटेक इनोवेशन प्रा. लि., पुणे (महाराष्ट्र) द्वारा किया जा रहा है, जिसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से मतदाताओं को भेजा जा रहा है। साथ ही, मतदाता द्र-श्वक्कढ्ढष्ट भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र संकट में, प्रशासन बना मूकदर्शक

सूरजपुर/भैयाथान/मूक पत्रिका

जहां एक ओर सरकार सबका साथ, सबका विकास का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की ग्राम पंचायत रजनी में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की उपेक्षा की कहानी सरेआम उजागर हो रही है। टूटे हुए पुल और जर्जर सड़कों से परेशान लगभग 260 आदिवासी ग्रामीण जिन्हें देश के राष्ट्रपति द्वारा ÷दत्तक ग्राम÷ का गौरव प्राप्त है आज बुनियादी सुविधाओं से वंचित होकर संघर्ष कर रहे हैं, जबकि प्रशासन मौन मुद्रा में तमाशा देख रहा है।

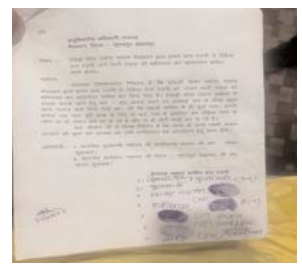

पावर प्लांट बना मुसीबत की जड़-रजनी से टेढ़िया पारा को जोड़ने वाली संपर्क सड़क पर हाईड्रो पावर प्लांट के भारी वाहनों और लापरवाह निर्माण कार्यों ने सड़क को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। बरसात में सड़क बह गई, आवाजाही ठप हो गई, लेकिन प्लांट प्रबंधन से लेकर प्रशासन तक सब चुप हैं।

नेताओं का फूटा गुस्सा, लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी-भाजपा युवा मोर्चा भैयाथान मंडल अध्यक्ष अमन प्रताप सिंह ने कहा, यह अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हम संघर्ष करेंगे और राष्ट्रपति के दत्तक ग्राम की वास्तविक स्थिति को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे।पूर्व जनपद सदस्य एवं सभापति अभय प्रताप सिंह ने भी कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि आवेदन और निवेदन करके देख लिए। अब यदि तत्काल संज्ञान नहीं लिया गया तो हम दत्तक पुत्रों के साथ सड़क पर उतरेंगे और जनांदोलन करेंगे।

विकास की हकीकत देखनी हो तो आइए रजनी-विकास के नाम पर वाहवाही लूटने वाले अफसर और जनप्रतिनिधि आज नदारद हैं। जमीनी सच्चाई यह है कि बच्चों की पढ़ाई, मरीजों की चिकित्सा और रोजमर्रा का जीवन तक अवरुद्ध हो गया है। क्या यह वही दत्तक ग्राम है जिसका वादा था कि आदर्श गांव बनाकर मिसाल पेश की जाएगी? अब सवाल उठता है कि जब राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की भी कोई सुनवाई नहीं, तो आम जनता की कौन सुनेगा? कब तक गांववासी टूटी सड़कों और प्रशासनिक चुप्पी की मार झेलते रहेंगे? प्रशासन जवाब दे... पावर प्लांट जिम्मेदार कब जागेगा? क्या विकास सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा?

नशे के विरुद्ध बस्तर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, बोधघाट थाना क्षेत्र का है मामला नशीली दवाई का विक्रय करते हुए आरोपी को बस्तर पुलिस ने किया गिरफ्तार

एयरपोर्ट के पीछे कर रहा था नशीली दवाई का तस्करी, पूर्व में चोरी जैसे अपराधों में रहा है शामिल

जगदलपुर /मूक पत्रिका

पुलिस अधीक्षक, शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा अपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में एक व्यक्ति को नशीली दवाई विक्रय करते हुए गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। कि दिनाक 05.06.2025 को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि एयरपोर्ट के पीछे एक व्यक्ति अपने अधिपत्य के झोला में अवैध रूप से नशीली दवाई करने हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाप पुलिस टीम के द्वारा एयरपोर्ट के पीछे पहुंच कर देखने पर एक व्यक्ति रोड किनारे खड़ा मिला जो पुलिस को देखकर भागने लगा गया जिसे घेराबंदी कर पकडे जाने पर नाम पता पूछने पर अपना नाम दशरथ सिंह राजपुत पिता शरद सिंह राजपुत, उम्र 20 वर्ष निवासी राजेन्द्र नगर वार्ड, जगदलपुर जिला बस्तर छ0ग0 का रहने वाला बताये आरोपी के अधिपत्य के झोले की तलाशी लेने पर अल्पराजोलम टेबलेट 30 पत्ता किमती 660/- रूप्ये एवं विनसिरेक्स कॅफ सिरफ 26 नग सीसी किमती 4680/-रूपये को बरामद कर जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 21 (ख) एनडीपीएस एक्ट का पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया एवं न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने रवाना किया गया।महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी- निरीक्षक - लीलाधर राठौरउ. नि. - ललित नेगी, लोकेश्वर नागप्र.आर. - पवन, अहिलेश नागआरक्षक - ह ो र ी लाल, मुकेश कोडोपी, भैरव सिन्हा, विजय तिर्कीनाम आरोपी =- दशरथ सिंह राजपुत पिता शरद सिहं राजपूत, उम्र 20 वर्ष, निवासी राजेन्द्र नगर वार्ड जगदलपुर।

जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की पहल, जिले में 'मोर गांव मोर पानी' अभियान के तहत जल संरचनाओं का निर्माण तेज़

कलेक्टर रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन में जल संरक्षण कार्यों को मिल रही नई दिशा

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जल संरक्षण आज केवल एक पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि सतत विकास और भावी पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा एक संवेदनशील विषय बन चुका है। इसी दृष्टिकोण से कलेक्टर रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम ग्रामीण अंचलों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। इस क्रम में 'मोर गांव मोर पानी' अभियान को विशेष रूप से प्रभावशाली रूप में लागू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से न केवल संरचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं, बल्कि जन सहभागिता को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणों को जल संरक्षण की आवश्यकता और तकनीकी विधियों की जानकारी दी जा रही है। इसके लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रशिक्षित किया गया है, ताकि वे स्थानीय स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन कर सकें। विशेष रूप से ग्राम पंचायत तिलई (जनपद पंचायत बेरला) में जल संरक्षण हेतु उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। यहाँ रिचार्ज पिट, तालाब गहरीकरण, और नवीन तालाब निर्माण जैसे कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए हैं। ये संरचनाएं न केवल वर्षा जल के संचयन में मददगार हैं, बल्कि भूजल स्तर को पुनः भरने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

यह अभियान जिले के अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में जल संरक्षण की दिशा में ठोस और दीर्घकालीन प्रयास करे। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कहा कि जल ही जीवन है यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जिला प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल संरक्षण कार्य केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित न रह जाएं, बल्कि इसे जन आंदोलन के रूप में विकसित किया जाए। 'मोर गांव मोर पानी' जैसे अभियान इसी दिशा में एक ठोस कदम हैं।जल संरक्षण के प्रति इस सजगता और सक्रियता से न केवल पर्यावरणीय संतुलन बेहतर होगा, बल्कि ग्रामीणों की जल संबंधी समस्याओं का भी स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। आने वाले समय में यह पहल बेमेतरा को जल-सुरक्षित जिला बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ दंतेवाड़ा ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंप ज्ञापन

दंतेवाड़ा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ दंतेवाड़ा ने जिलाध्यक्ष चंचल कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को अपनी जायज मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य मंत्री ने कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया ।इस कार्यक्रम में प्रांतीय सचिव आर के जाटव,कार्यकारी अध्यक्ष बालसिंह नेताम,सचिव मोहन समरथ,उपाध्यक्ष एमन ठाकुर ,अमल साय बघेल,जिला चिकित्सालय अध्यक्ष लक्ष्मण ठाकुर,कमलेश नाग,अंकुश कवर,मोहन बघेल ,शंकर , चेलम जगन्नादम,दीपक ठाकुर एवं समस्त कर्मचारी उपस्थित थे।

चांदनी क्षेत्र का संजिवनी बंद : कुपोषित बच्चों की एकमात्र आशा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी

सूरजपुर/मूक पत्रिका

कुपोषण से जूझते बच्चों के लिए एकमात्र संजीवनी कहे जाने वाला पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) बिहारपुर, सरकारी उपेक्षा और संवेदनहीनता का शिकार हो गया है। 18 जनवरी 2023 को शुरू हुआ यह केंद्र मात्र व्हाट्सएप संदेश के जरिए 5 फरवरी 2025 को बंद कर दिया गया न कोई अधिसूचना, न कोई स्पष्टीकरण।

वेतन नहीं, इंसाफ नहीं, कर्मचारी ठगे गए-इस केंद्र में कार्यरत एएनएम पार्वती यादव, जिनकी उम्र अब 42 हो चुकी है, आज रोजगार की तलाश में भटक रही हैं। दो वर्षों तक सेवा देने के बावजूद जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक का वेतन उन्हें नहीं मिला। अब सवाल है, उन्हें रोजगार कौन देगा? क्या यह सरकार द्वारा किसी महिला कर्मचारी के भविष्य से किया गया मजाक नहीं?

हितग्राही ठगे गए,132 बच्चों की मांओं को नहीं मिली प्रोत्साहन राशि-केंद्र बंद होने से पूर्व दिसंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच 132 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की माताएं, 15-20 दिन तक केंद्र में रुककर अपने बच्चों को सुपोषित करने का प्रयास करती रहीं। लेकिन उन्हें 2250 रुपये की प्रोत्साहन राशि आज तक नहीं दी गई। 13 पण्डो' जनजातीय हितग्राही, जो शासन की प्राथमिकता सूची में हैं, वे भी इसी अन्याय के शिकार बने हुए हैं।

भ्रष्टाचार की बू और जनदर्शन की अनदेखी-केंद्र के कर्मचारी तुलेश्वर जायसवाल द्वारा मुख्यमंत्री जनदर्शन और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की आशंका जताई गई है।

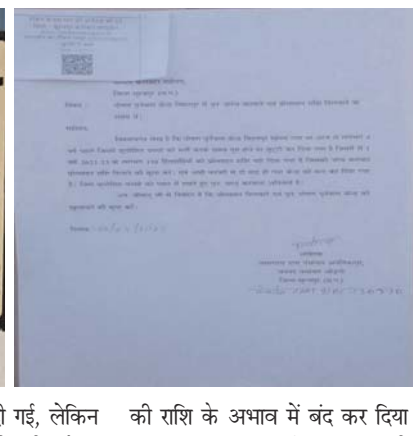

24 मार्च 2025 को उपसरपंच तुलसी जायसवाल द्वारा कलेक्टर सूरजपुर को शिकायत दी गई, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

विधायक ने शुरू किया, मंत्री ने बंद कर दिया?-यह केंद्र 1 जनवरी 2022 को तत्कालीन विधायक पारसनाथ राजवाड़े द्वारा शुरू किया गया था, जो चांदनी क्षेत्र के बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ। लेकिन सरकार बदलते ही, क्षेत्रीय विधायक महिला एवं बाल विकास मंत्री होते हुए भी यह केंद्र कुछ लाख की राशि के अभाव में बंद कर दिया गया। क्या यह सामाजिक न्याय की हत्या नहीं?

बैजनपाठ, लुल्ह, भूड़ा जैसे अंतिम छोर के गांव - फिर से अंधेरे में-इन सुदूर अंचलों में कुपोषण सबसे बड़ा शत्रु है। मगर अफसोस कि जनप्रतिनिधियों की भाषणों में विकास होता है, जमीन पर नहीं।कुपोषण से पीड़ित इन गांवों के बच्चों के लिए अब कोई सहारा नहीं बचा।

जवाब कौन देगा?-क्यों बंद हुआ यह केंद्र एक व्हाट्सएप मैसेज से? कर्मचारियों का 9 माह का वेतन कहां गया? 132 हितग्राहियों की प्रोत्साहन राशि किसकी जेब में? पार्वती यादव का भविष्य कौन लौटाएगा? क्या यह सब सिर्फ सत्ता परिवर्तन का साइड इफेक्ट है?

सरकार जवाब दे, जनता जानना चाहती है-पोषण पुनर्वास केंद्र केवल एक इमारत नहीं था, यह सैकड़ों बच्चों की उम्मीद थी।उम्मीद है प्रशासन, महिला बाल विकास विभाग, और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए केंद्र को पुनः प्रारंभ करने, बकाया वेतन और प्रोत्साहन राशि देने की पहल करेंगे। वरना यह सुपोषण अभियान सिर्फ बैनर तक सीमित रह जाएगा और ज़मीनी हकीकत भूख और उपेक्षा की कहानियों में तब्दील हो जाएगी।

अधिकारियों ने किया हरी झंडी दिखाकर रवाना, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह

श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत जिले से 62 तीर्थयात्री अयोध्या धाम के लिए हुए रवाना

बेमेतरा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी रामलला दर्शन योजना (अयोध्या धाम) के अंतर्गत जिले से चयनित श्रद्धालुओं का दल बीते बुधवार को कलेक्टर रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन में अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। इस योजना के अंतर्गत शासन द्वारा 62 तीर्थयात्रियों (जिसमें 02 अनुरक्षक शामिल हैं) का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य के अनुसार जिले के जनपद पंचायत बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़ से 48 तीर्थयात्री तथा नगर पालिका परिषद् बेमेतरा एवं नगर पंचायत थानखम्हरिया, नवागढ़, भिमौरी, कुसमी एवं दाढ़ी से 12 तीर्थयात्री चयनित किए गए। प्रातः 07 बजे सभी तीर्थयात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण कलेक्टोरेट भवन के दृष्टि सभाकक्ष में किया गया। इसके बाद 07:30 बजे जिला कलेक्टोरेट परिसर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रेमलता मंडावी, अपर कलेक्टर अनिल वाजपेयी तथा उप संचालक समाज कल्याण विभाग के द्वारा हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को दो बसों के माध्यम से राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात श्रद्धालुओं को नगर पालिका अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा, जनपद पंचायत बेमेतरा अध्यक्ष श्रीमती हेमा दिवाकर, अपर कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत एवं समाज कल्याण उपसंचालक द्वारा सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। श्रद्धालुओं में उत्साह और श्रद्धा का विशेष भाव देखा गया। सभी यात्रीगण निर्धारित कार्यक्रमानुसार राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से विशेष रेलगाड़ी द्वारा अयोध्या धाम में श्री रामलला के दर्शन हेतु रवाना हो चुके हैं।

यात्रा पूर्ण होने के पश्चात यह दल 09 अगस्त 2025 की देर रात तक बेमेतरा लौटेगा। यह आयोजन कलेक्टर रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन में सुचारु रूप से संपन्न हुआ, जिसमें प्रशासन की ओर से सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा की सभी आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित की गई थीं। श्री रामलला के दर्शन हेतु रवाना हुए श्रद्धालुओं ने प्रदेश शासन और जिला प्रशासन का आभार प्रकट किया।

आज ही जुड़े हमारे राष्ट्रीय दैनिक अखबार मूक पत्रिका एवं न्यूज नेटवर्क के साथ
आवश्यकता
कवर्धा, कांकेर (उत्तर बस्तर), कोरबा, कोरिया, जशपुर, जांजगीर-चाँपा, मनेन्द्रगढ़, सक्ती, सारंगढ़, मोहल्ला मानपुर, दन्तेवाड़ा (दक्षिण बस्तर), दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, बस्तर, महासमुंद, राजनांदगाँव, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा, बलौदाबाजार, बालोद, मुंगेली, बेमेतरा, सुरजपुर, गरियाबंद, सुकमा, बलरामपुर, नारायणपुर, बीजापुर, गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही
राष्ट्रीय अखबार मूक पत्रिका सम्पर्क करें। +91 7999238079, 6267320220 Head Office : Press Road & Media HouseTelibandha Shyam Nagar Raipur Chhattisgarh-492001 इच्छुक व्यक्ति सम्पर्क करें।

राष्ट्रीय दैनिक मूक पत्रिका निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज... MP National News
छतीसगढ़ के संभाग/ जिला/ब्लॉक/ग्रामीण स्तर पर मिडिया मित्र के रूप में कार्य करने हेतु सम्पर्क करें। 9770269285, 7999238079
कवर्धा, कांकेर (उत्तर बस्तर), कोरबा, कोरिया, जशपुर, जांजगीर-चाँपा, मनेन्द्रगढ़, सक्ती, सारंगढ़, मोहल्ला मानपुर, दन्तेवाड़ा (दक्षिण बस्तर), दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, बस्तर, महासमुंद, राजनांदगाँव, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा, बलौदाबाजार, बालोद, मुंगेली, बेमेतरा, सुरजपुर, गरियाबंद, सुकमा, बलरामपुर, नारायणपुर, बीजापुर, गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही
राष्ट्रीय अखबार मूक पत्रिका सम्पर्क करें। +91 7999238079, 6267320220 Head Office : Press Road & Media HouseTelibandha Shyam Nagar Raipur Chhattisgarh-492001 इच्छुक व्यक्ति सम्पर्क करें।

MP National News राष्ट्रीय दैनिक मूक पत्रिका निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...
इच्छुक व्यक्ति जल्द सम्पर्क करें।
Contact No.+91 7999238079, 9770269285, 6267320220
Head Office : Press Road & Media HouseTelibandha Shyam Nagar Raipur Chhattisgarh-492001

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा स्वामी डीबी कार्प लिमिटेड के लिए प्लाट नम्बर 40/44 इंडस्ट्रियल एरिया बीरगांव रोड, उरला, रायपुर से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।